https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'हम गरीबी-मुक्त एवं वैभव-युक्त भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं'

वर्ष-13, अंक-16 16-30 सितम्बर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

अजेय भारत, अटल भाजपा

कृषि क्षेत्र में सुधारों का एक नया युग शुरू

नए भारत के निर्माण का संकल्प

शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की झलकियां

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल व अन्य

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित करें: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 8 एवं 9 सितंबर 2018 को डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में संपन्न हुई।

वैचारिकी

संस्कृति और समाज 25

लेख

शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश 28

साक्षात्कार

के. जे. अल्फोंस, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 30

अन्य

हम गरीबी-मुक्त एवं वैभव-युक्त भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं: नरेन्द्र मोदी 23

2018-19 की प्रथम तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि 27

भाजपा संगठन चुनाव अगले वर्ष तक स्थगित 29

'छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में अटलजी का योगदान अतुलनीय' 32

'भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता एक समर्पित योद्धा है' 33

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

व्यंग्य चित्र 04

10 सुशासन की अवधारणा को फलीभूत करनेवाले एक युगद्रष्टा का अवसान

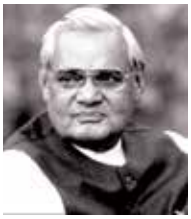

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पहले दिन 8 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री एवं पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री...

12 कृषि क्षेत्र में सुधारों का एक नया युग शुरू

डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 9 सितंबर...

17 नए भारत के निर्माण का संकल्प

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 9 सितंबर...

22 भारत को अवैध घुसपैठियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

देश का हर नागरिक हमारे मेहनतकश किसानों का आभारी है। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

@AmitShah

एमएसपी दरों में ऐतिहासिक वृद्धि के बाद मोदी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने और पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के रूप में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। इससे कड़ी परिश्रम करने वाले हमारे किसान भाईयों को बहुत लाभ मिलेगा।

@Ramlal

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) के मुद्दे पर संसदीय समिति को स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा सर्वाधिक ग़लत तरीक़े से बड़े लोन UPA के शासन काल में दिए गए। NPA की ज़िम्मेदार कांग्रेस है।

facebook

चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने जिस आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना की शुरुआत की थी, उसके सफल परिणाम अब जनता के सामने हैं। इस योजना के तहत प्रदेश भर में वेलनेस सेन्टर के रूप में परिवर्तित कुल 891 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, एलोपैथी और योगा तीनों प्रकार का इलाज आम जन को सुगमता से उपलब्ध करवाया जा रहा है। — **वसुंधरा राजे**

गरीबी के विरुद्ध लड़ाई हम सभी का साझा संघर्ष है। आइए, हम सब मिलकर इसे मिटाने के लिए कदम बढ़ाएं।

— **शिवराज सिंह चौहान**

केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दिया जा रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ शौचालय आदि सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। — **योगी आदित्यनाथ**

व्यंग्य चित्र

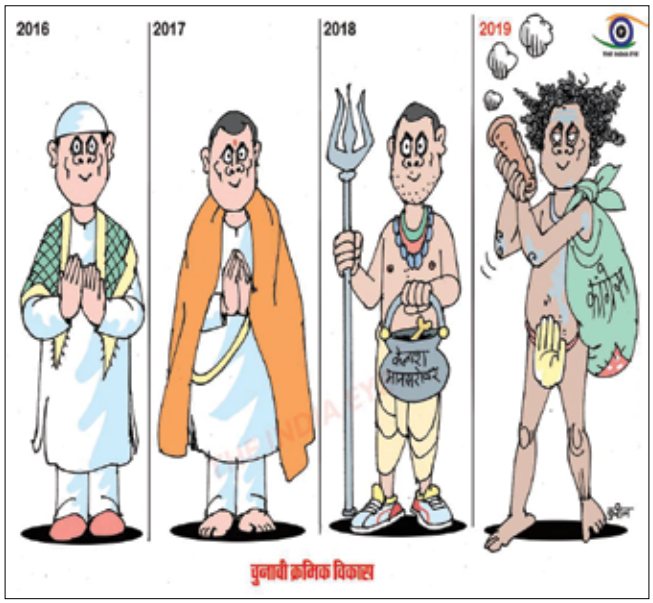

सभार : सोशल मीडिया

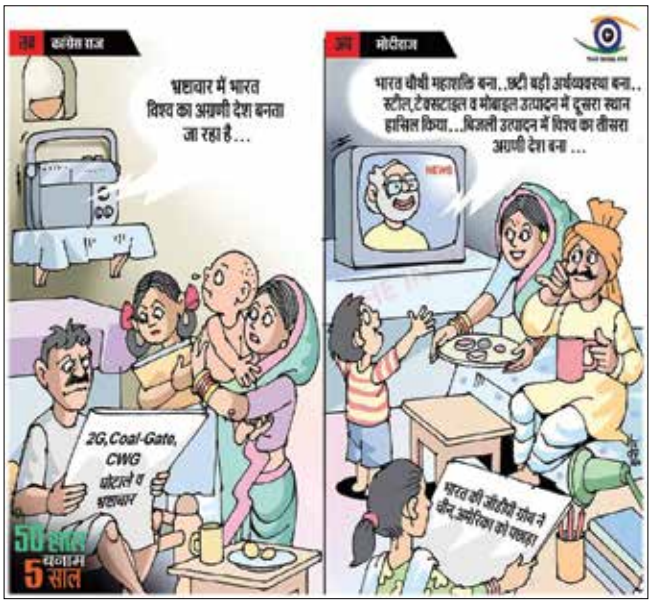

भारत : उत्तरोत्तर विकास के पथ पर

'अजेय भारत, अटल भाजपा' का संदेश 08–09 सितंबर 2018 को दिल्ली में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से देश को मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व में देश में विकास ने जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी है, उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही हैं। चार वर्षों के निरंतर सुधार, सुशासन तथा भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर लगातार कुठाराघात से देश में चहुंमुखी बदलाव के एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। आज जबकि भारत की विश्वसनीयता एवं इसका कद पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है, पूरा विश्व एक नये भारत के उदय को देख रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना उचित स्थान पाने को तत्पर है।

देश मोदी सरकार के नेतृत्व में हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गरीब, वंचित, महिला एवं युवाओं के लिये सरकार की प्रतिबद्धता अनेक अभिनव कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। गांव से लेकर शहरों तक आम जन–जीवन में काया–कल्प किया जा रहा है। गरीब से गरीब के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना एवं वित्तीय समावेशन से लेकर हर घर में गैस कनेक्शन एवं शौचालय की योजना से एक नये भारत की तस्वीर उभर रही है जिसके केन्द्र में गरीब, वंचित, महिला एवं युवा हैं। आज जबकि भारत एक 'पॉवर सरप्लस', देश बन चुका है, एक भी गांव ऐसा नहीं बचा, जहां बिजली ना पहुंची हो और हर घर में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आरोग्य एवं स्वस्थ जीवन का संदेश से जहां विश्व गुंजायमान है, वहीं 'आयुष्मान भारत' से पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन कर समाज के गरीब से गरीब तबके को चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने का संकल्प मोदी सरकार ने दिखाया है। किसान एवं ग्रामीण समाज अब असंख्य अवसरों का अनुभव कर रहे हैं तथा किसानों की आय को दुगुना करने के संकल्प के साथ खेती में अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग अब सुगम बनाया जा रहा है।

मोदी सरकार की अतुलनीय उपलब्धियों तथा करोड़ों लोगों के जीवन में अभिनव योजनाओं एवं कार्यक्रमों से खुशियां भरने के प्रयासों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ठीक ही प्रशंसा की है। कृषि पर लाये गये प्रस्ताव ने किसानों को आय दुगुनी करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है। राजनैतिक प्रस्ताव में एक महान राष्ट्र के उदय से भारत के प्रति विश्व के बदलते नजरिये का संज्ञान लिया गया है।

आज जबकि काले धन के विरुद्ध युद्ध का परिणाम आने लगा है, बढ़ी हुई आर्थिक विकास दर से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है और दुनिया के दूसरे देश अब भारत के भविष्य के प्रति विश्वास से देख रहे हैं। पिछली तिमाही में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर सभी पूर्वानुमानों से कहीं आगे रही तथा इससे यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि भारत भारी आर्थिक विकास दर प्राप्त करने को अब तैयार है। 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' में भारत की छलांग, 'मूडी' द्वारा इसके स्तर में सुधार, विश्व बैंक एवं आइएमएफ द्वारा समय–समय पर सराहना इस बात को प्रमाणित करता है कि राजनैतिक इच्छाशक्ति से भरा नेतृत्व देश में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। कांग्रेस–नीत यूपीए शासन में नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार, घपलों एवं घोटालों से त्रस्त निराशा एवं नकारात्मकता के वातावरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबार कर मंदी की मार झेल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक 'चमकता हुआ सितारा' के रूप में स्थापित करने का श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है।

मोदी सरकार की अतुलनीय उपलब्धियों तथा करोड़ों लोगों के जीवन में अभिनव योजनाओं एवं कार्यक्रमों से खुशियां भरने के प्रयासों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ठीक ही प्रशंसा की है। कृषि पर लाये गये प्रस्ताव ने किसानों को आय दुगुनी करने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है। राजनैतिक प्रस्ताव में एक महान राष्ट्र के उदय से भारत के प्रति विश्व के बदलते नजरिये का संज्ञान लिया गया है। कार्यकारिणी ने सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करते हुए एक शोक प्रस्ताव पारित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आने वाले विधानसभा चुनावों एवं भावी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी संगठनात्मक चुनाव एक वर्ष के लिये बढ़ा दिये गये हैं। इस कार्यकारिणी से भाजपा बेघरी, बेरोजगारी, गरीब, बीमारी से मुक्त एक नये भारत का 2022 तक निर्माण के संकल्प के साथ निकली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नया भारत एकजुट, समृद्ध, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से संभव है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित करें: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 8 एवं 9 सितंबर 2018 को डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने बैठक के पहले दिन 8 सितंबर को सारगर्भित एवं दूरदर्शी अध्यक्षीय भाषण किया। श्री शाह ने अपने उद्बोधन में जहां संगठन को और सशक्त बनाने पर बल दिया, वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपानीत केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट हो भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया। हम अध्यक्षीय भाषण का मुख्य अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान के बाद पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि श्री अटल जी के देश के विकास में और पार्टी के प्रति योगदान को शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस बैठक के माध्यम से न केवल अटल जी को याद करते हैं, बल्कि उनके बताये रास्ते पर चलने के विनम्र प्रयास का संकल्प भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनके देहावसान से न केवल भाजपा बल्कि पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में जो रिक्तता आई है, इसे भर पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अटल जी एक संवेदनशील कवि, अजातशत्रु नेता, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री और भारतीय भाषाओं के प्रेमी होने के साथ-साथ वे एक जन्मजात देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से संसद ने पांच दशकों तक लोकतंत्र के मंदिर में जनता की आवाज बनने वाले जागरूक सदस्य को खो दिया है। उन्होंने कहा कि अटल जी की स्वीकृति न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी दलों में व्यापक रूप से थी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी तीन बार प्रधानमंत्री बने और अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसे कई फैसले उन्होंने लिए जो लंबे समय तक याद रखे जायेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, राज्यसभा के चुनाव को पारदर्शी बनाना, डोनर मंत्रालय का गठन करके उत्तर-पूर्व के विकास को प्राथमिकता देना, जनजाति मंत्रालय का अलग से गठन करना, छोटे राज्यों का गठन कर वहां विकास की गति को आगे बढ़ाना; ऐसे ही कुछ प्रमुख फैसले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरीकी दवाब के बावजूद 1998 में गोपनीय तरीके से परमाणु

विस्फोट और कारगिल विजय के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी ने भारतवर्ष को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में अटलजी का नाम अमर रहेगा, वे सच्चे अर्थों में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे भारतवर्ष के शिखर पुरुष थे। उन्होंने कहा कि श्री अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ी और उनके ही आशीर्वाद से आज 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी को जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आज अटलजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य, संदेश और प्रेरणा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केरल सदी की सबसे भयानक बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के कार्यकर्ता पूरी संवेदना और सेवा भावना के साथ केरल की जनता के साथ खड़े हैं और उनकी सेवा में तत्परता के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

श्री शाह ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी बैठक से लेकर आज तक के दौरान देश में हुए लगभग सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय यात्रा को जारी रखी है। उन्होंने कहा कि गुजरात, हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में हमें विजयश्री प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल में तो हमें 50% से अधिक वोट मिले हैं, नागालैंड में हमने पहली बार सबसे अधिक 12 सीटें जीती हैं और हमारे उपमुख्यमंत्री बने हैं, मेघालय में भी हम सरकार में सहयोगी हैं और त्रिपुरा में तीन चौथाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई है जहां पहले हम एक भी सीट जीत नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, हमें 104 सीटों पर विजय प्राप्त होने के साथ सबसे अधिक वोट मिले, बहुमत से केवल हम 6 सीटें दूर रहे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि देश के 70% भू-भाग पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सेवा करने का अधिकार दिया है, यह हमारे लिए काफी आनंद का विषय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भ्रांतियां और झूठ फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में गतिरोध उत्पन्न करने की कुचेष्टा की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन यह निर्णय ले लिया कि हम विपक्ष के इस झूठे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे और विपक्ष को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है, जब सरकार अल्पमत में आ जाए या जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश हो, सड़कों पर जनता द्वारा सरकार के कामकाज के खलाफ आंदोलन हो रहे हों, भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हों, लेकिन मोदी सरकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि देश की जनता 2014 से भी अधिक दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ अडिग भाव से खड़ी है, हम दो तिहाई बहुमत के साथ सदन में विजयी हुए। उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दलों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा और जनता को भी यह मालूम पड़ा कि विपक्ष किस प्रकार सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रही है।

> कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष देश में जातिवाद, तुष्टीकरण और सरकार के खिलाफ दुर्भावना की राजनीति कर रहा है लेकिन देश की जनता हर चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब दे रही है। विपक्ष की महागठबंधन एक ढकोसला मात्र है। 2014 में भी ये सभी दल हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़े थे और हारे थे। 2019 में इन्हें 2014 से भी बड़ी हार मिलने वाली है।

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष देश में जातिवाद, तुष्टीकरण और सरकार के खिलाफ दुर्भावना की राजनीति कर रहा है लेकिन देश की जनता हर चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब दे रही है। सत्ता प्राप्ति की स्वार्थसिद्धि के लिए विपक्ष के महागठबंधन बनने की चर्चा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन एक ढकोसला मात्र है। उन्होंने कहा कि 2014 में भी ये सभी दल हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़े थे और हारे थे। 2019 में इन्हें 2014 से भी बड़ी हार मिलने वाली है। उन्होंने पार्टी के नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के झूठे प्रचार का डटकर सामना करें और जनता के बीच उनको बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे खिलाफ चाहे कितना भी दुष्प्रचार करे, हम विकास के मार्ग पर अनवरत चलते रहेंगे और विकास के प्रति हमारी आस्था और गहरी होती रहेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी बैठक से इस बैठक तक मोदी सरकार ने विकास के कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों से किसानों की समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के पसीने के मूल्य और देश के विकास में उनके योगदान को भलीभांति जानती है और उनकी समस्याओं को भी समझती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुने से भी अधिक की वृद्धि कर किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में मजबूत

कदम बढ़ाने का काम किया है।

आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है, जो इतने बड़े व्यापक स्तर पर विश्व की पहली ऐसी योजना है। उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को इस योजना को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने की वर्षों से पड़ी लंबित मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य भी मोदी सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की, राज्य सभा में तो उन्होंने इस विधेयक को पारित ही होने नहीं दिया था, लेकिन जनता के आशीर्वाद से हम इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने में कामयाब रहे।

पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के मानचित्र पर हुए व्यापक बदलाव की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब हम अर्थव्यवस्था की वैश्विक सूची में 9वें स्थान पर थे, जबकि आज हम 6ठे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम तेज गति से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगाई जा सकी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हमने 8.2% की दर से विकास दर हासिल कर फिर से दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल किया है।

जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब हम अर्थव्यवस्था की वैश्विक सूची में 9वें स्थान पर थे, जबकि आज हम 6ठे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम तेज गति से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगाई जा सकी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश की 60% से अधिक आबादी अर्थतंत्र की मुख्यधारा से काफी समय तक वंचित रही। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवा देश के सुदूर गांव, गरीब, दलित, पिछड़े तबके तक पहुंच ही नहीं पाती थी, अब पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में तब्दील कर दिए जाने से अर्थव्यवस्था में व्यापक और सकारात्मक बदलाव होंगे और विकास की मुख्यधारा से ये जुड़ पायेंगे।

कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल विकास किया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, यूरिया की किल्लत को सदा के लिए ख़त्म की योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन से लैब को लैंड तक पहुंचाने की योजना, ई-मंडी के माध्यम से फसलों की क्रय-बिक्री के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और प्रधानमंत्री फसल बीमा से कृषि की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रति देश के नागरिकों में जागरूकता फैलाने का भी अनुरोध किया और कहा कि हमें किसानों को फसल बीमा दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित परियोजनाओं को गति देकर सरकार ने देश के बड़े भू-भाग को खेती के लिए उपयुक्त बनाने का कार्य किया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तीन लाख से अधिक फर्जी कंपनियों को बंद करके काले धन के संग्रह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है और बेनामी संपत्ति के लिए कड़े क़ानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से इनकम टैक्स में लगभग दोगुना वृद्धि हुई है और टैक्स कलेक्शन 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 10.02 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह जीएसटी के लागू होने से भी प्रक्रिया काफी आसान हुई है। साथ ही, टैक्स कलेक्शन में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काफी उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि JAM के उपयोग से पारदर्शी व्यवस्था की नींव रखी गई है जिससे 33 हजार करोड़ रुपये के मूल्य सामान की खरीदी महज 11 हजार करोड़ रुपये में ही की गई है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के विकास की दिशा बदली है और 126 से अधिक लोक-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों तक विकास को पहुंचाने की योजना कार्यान्वित की है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 5.5 करोड़ गैस सिलिंडर वितरित किये गए हैं, लगभग एक करोड़ घर का निर्माण किया गया है, 6.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, बिजली से वंचित लगभग 18 हजार गांवों और सवा दो करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है, जेनरिक दवाई की दुकान से गरीबों को सस्ती दवाइयां मुहैया कराई जा रही है और मिशन इन्द्रधनुष योजना के माध्यम से 18 करोड़ से अधिक गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का महती कार्य अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा देश के लगभग 65 हजार गांवों में सात लोक-कल्याणकारी योजनाओं

को शत-प्रतिशत पूरा करने का अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और 2019 के लोक सभा चुनाव के पहले-पहले हम देश के लगभग 1 लाख 20 हजार गांवों में इन सभी सातों योजनाओं को शत-प्रतिशत क्रियान्वित करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक किसी भी कांग्रेस सरकार ने समस्या मुक्त गांव की कल्पना नहीं की जबकि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' सिद्धांत पर चलते हुए गांवों को समस्यामुक्त करने का बीड़ा उठाया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व मंच को भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देख कर सभी भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व जलवायु सम्मेलन में भारत की निर्णायक भूमिका, दाभोस परिषद् का उद्घाटन भाषण देने का सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की बढ़ती भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की वैश्विक स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक स्वर से आज यह कह रहा कि आने वाली सदी भारत की है, इसमें कोई संशय नहीं है।

कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 'मेक इन इंडिया' का नारा देते हैं तो कांग्रेस पार्टी 'ब्रेक इन इंडिया' में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर घोलकर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता उचित जवाब देगी।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि NRC पर हमारा मत बिलकुल स्पष्ट है। एक-एक घुसपैठिये की पहचान की जायेगी और उन्हें भारत से बाहर किया जाएगा। देशहित के ऊपर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की साजिश को देश के जनता भलीभांति जानती है, कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि जब हमने एनआरसी पर कड़ा रुख इख्तियार किया, तो कांग्रेस पार्टी को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उन्होंने कहा कि हम सिटिजनशिप एक्ट लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख और इसाई शरणार्थियों को भारत में शरण दी जायेगी, उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जायेगी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पर भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष वोटबैंक की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई इस्लामिक देशों में भी ट्रिपल तलाक को तलाक दे दिया गया है, लेकिन भारत में विपक्ष इसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सभा में कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने वाले क़ानून को लटकाकर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एनआरसी पर कांग्रेस को अपने कदम वापस करने पर मजबूर होना पड़ा, इस विषय पर भी उन्हें अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे, क्योंकि यह महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

देश में माओवादियों की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने देश को अस्थिर करने के लिए भारी हथियार खरीदने, नक्सलवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं लेकिन पूरी निर्लज्जता के साथ विपक्ष राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले ऐसे लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार और राज्य प्रशासन को बधाई देता हूं जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने देश की सुरक्षा की दिशा में कड़े कदम उठाये हैं। उन्होंने विपक्ष को देश की सुरक्षा के ऊपर वोटबैंक की राजनीति को तरजीह दिए जाने के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि देश की जनता पूरे घटनाक्रम को देख रही है और वह इस अपराध के लिए विपक्ष को कभी माफ़ नहीं करेगी।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले समय में पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में हमारी स्थिति पिछली बार से भी अधिक मजबूत हुई है। इन पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े विजय की ओर अग्रसर है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट हो भाजपा की प्रचंड विजय सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

> 2019 का लोक सभा चुनाव भी अब दूर नहीं रह गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश के 19 राज्यों में हमारी सरकार है और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं हैं, उनमें हम दूसरे स्थान पर काबिज हैं। मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय और परिश्रमी नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2019 का लोक सभा चुनाव भी अब दूर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश के 19 राज्यों में हमारी सरकार है और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं हैं, उनमें हम दूसरे स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय और परिश्रमी नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 2019 के लोक सभा चुनाव में पिछली बार से भी अधिक बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे, 2019 के चुनाव में हमारी विजय निश्चित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उन 120 लोक सभा सीटों पर जीत दर्ज करने का आह्वान किया, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी जीत नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनाव में हमारी विजय सर्वोच्च नहीं है, बल्कि 2019 के चुनाव में हमारा सर्वोच्च आना बाकी है। ■

अटलजी की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित

सुशासन की अवधारणा को फलीभूत करनेवाले एक युगद्रष्टा का अवसान

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पहले दिन 8 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री एवं पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव ने रखा। इस शोक प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा यह संकल्प लेती है कि वह अटलजी के दिखाए मार्ग पर सतत चलती रहेगी तथा देश में सुशासन और विकास की राजनीति को मजबूती के साथ आगे बढ़ायेगी। हम यहां शोक प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्र के सर्वप्रिय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है। अटल जी के निधन से हम सभी ने इस देश में मूल्यनिष्ठ राजनीति के आधार पर सुशासन की अवधारणा को फलीभूत करनेवाले एक युगद्रष्टा को खोया है।

स्वाधीन भारत के राजनीतिक इतिहास में अटलजी ने अपनी निष्ठा और अपने आदर्शवादी सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाकर एक ऐसा विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प खड़ा किया, जो राजनीति के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सफल सिद्ध हुआ है। अटल जी की राजनीति की इस विकास यात्रा में संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है। इस यात्रा को देखें तो पार्टी के उदयकाल में उन्हें कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष करना पड़ा। ऐसा देखने को मिलता है कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष भरे अनेक दौर का सामना किया। राजनीतिक अस्पृश्यता, संसाधनों का अभाव, संगठन खड़ा करने और उसका विस्तार करने में आयी अनगिनत बाधाएं, लेकिन इन सबसे जूझते हुए उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को एक विशिष्ट पहचान दी। साइकल पर सवार होकर पार्टी की सदस्यता करने हेतु प्रवास और यात्रा से लेकर पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने तक, संगठन कार्य से जुड़ा ऐसा एक भी काम नहीं होगा जो अटलजी ने नहीं किया हो। अटलजी एक ही समय बौद्धिक और सांगठनिक, दोनों ही कार्यों को निर्बाध रूप से सहज भाव में करने वाले विरले नेताओं में से एक थे ।

अटल जी का व्यक्तित्व बहु-आयामी था। एक प्रखर विचारक, प्रतिभाशाली कवि, सिद्धहस्त लेखक और पत्रकार, ओजस्वी वक्ता और श्रेष्ठ सांसद होते हुए अटलजी जनप्रिय नेता एवं दूरदर्शी तथा शासन के सफल नेतृत्वकर्ता भी बने। अटलजी ने राजनीति में विचारधारा के

महत्व को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने लोकहितों के प्रति निष्ठा और संवेदनशीलता का परिचय दिया तथा विपक्ष में रहते हुए एक आदर्श विपक्षी नेता का उदाहरण भी बने। संसद में और संसद के बाहर भी उन्होंने अपनी कार्यशैली से राजनीति की गरिमा को बढ़ाया और लोकतंत्र के प्रति विश्वास को मज़बूत किया। देश में गठबंधन-राजनीति की सफलता उन्होंने स्थापित की और 'गठबंधन धर्म' को निभाते हुए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।

सरकार में रहते हुए अटलजी ने जो कार्य किये हैं, उसके अनेक उल्लेखनीय आयाम हैं। विदेशमंत्री के नाते उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का महत्व और मर्यादाएं, दोनों का एहसास रखा और हमारी सामरिक स्थिति को लेकर उन्होंने विश्व की नजर में एक संतुलन की स्थिति पैदा करने का कार्य किया। भारत और इजरायल के साथ पारस्परिक सम्बन्धों का शिलान्यास अटलजी के कार्यकाल में ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने सभी देशवासियों को राष्ट्रीय गौरव और पहचान की अनुभूति दी ! जय जवान-जय किसान को जय विज्ञान से जोड़ते हुए उन्होंने आधुनिक सोच का उदाहरण दिया।

शासन की नीतियों में अटल जी का ज्ञानवृत्त अत्यंत बहुआयामी था। वे राजनीति, अर्थनीति, वैश्विक नीति और लोकनीति की गहरी समझ रखने वाले नेता थे। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण के विषय में भी उन्होंने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संतुलन की दृष्टि प्रस्तुत की। उनके कार्यकाल में आर्थिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण क़ानून लागू हुआ, परिणामतः देश के आर्थिक विकास को गति मिली। देश में महामार्गों तथा टेलीकम्यूनिकेशन के महाजाल निर्माण करने में उनकी दूरदृष्टि का बड़ा योगदान रहा है। सुविख्यात सुवर्ण चतुष्कोण और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी कई विकास योजनाएं उनकी दूरगामी सोच की परिचायक हैं। नदियों को जोड़ने की बात हो या फिर प्रवासी भारतीयों को अपने देश से जोड़ने की दिशा में उठाये कदम हों, अटल जी ने कई विषयों में विकास और सहभागिता के सूत्रों पर नई पहल की थी। उनके कार्यकाल में प्रारम्भ सर्व-शिक्षा अभियान के कारण स्कूलों के दाख़िलों बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी और शिक्षा का संख्यात्मक विस्तार तथा गुणात्मक विकास हो पाया था।

देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्धों के लिए भारत के राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखते हुए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए, जो सफल रहे। साथ ही उन्होंने अडिग रहते हुए भारत की सुरक्षा-दृष्टि से महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्य भी सफलतापूर्वक करके दिखाया।

अटलजी ने न केवल राजनीति को, बल्कि समूचे शासनतंत्र को ही सार्थक दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय मंत्रालय का नाम देकर एक नयी सोच का सृजन किया। स्वतंत्र रूप में जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने की पहल भी उनकी ही थी। देश के उपेक्षित पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से 'डोनर' मंत्रालय की स्थापना भी उनकी ही सोच का परिणाम था। देश के जनजाति बहुल और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को गति देनेवाले तीन नए राज्य — छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड — के बिना किसी विवाद के निर्माण का श्रेय भी अटलजी का ही है। अटल जी की सबको जोड़कर चलने की राजनीति के कारण ही यह तीनों राज्य बग़ैर कोई विवाद या हिंसा के बन पाए।

जब हम अटल जी के संघर्षों को याद करते हैं तो आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। अटलजी ने आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए लम्बी अवधि का कारावास स्वीकार किया। विपक्ष में रहते जिस अटल जी ने हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका ही निभायी, उन्ही अटलजी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकतांत्रिक सुधारों के लिए अनेक प्रयास किए। भारतीय संविधान के क्रियान्वयन की समीक्षा, राज्यसभा चुनाव में पारदर्शिता लाना और केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिमंडलों की सदस्य संख्या पर नियंत्रण, यह तीन महत्वपूर्ण सुधार अटलजी की सिद्धांतवादी सोच और कर्मठ कार्यशैली के उदाहरण हैं।

अटलजी के निधन से सभी प्रदेशों ने एक शासन की नीतियों को समझाने वाला एक सच्चा मार्गदर्शक खोया है। उन्होंने शासन के नेतृत्वकर्ता और पार्टी नेता, दोनों भूमिकाओं को न केवल कुशलतापूर्वक निभाया, बल्कि कुछ आदर्श भी स्थापित किए। उनके कार्य आज भी राष्ट्रीय राजनीति और शासन की कार्यपद्धति पर अपनी अमिट छाप की तरह हैं ।

अटलजी के निधन से सभी प्रदेशों ने एक शासन की नीतियों को समझाने वाला एक सच्चा मार्गदर्शक खोया है। उन्होंने शासन के नेतृत्वकर्ता और पार्टी नेता, दोनों भूमिकाओं को न केवल कुशलतापूर्वक निभाया, बल्कि कुछ आदर्श भी स्थापित किए। उनके कार्य आज भी राष्ट्रीय राजनीति और शासन की कार्यपद्धति पर अपनी अमिट छाप की तरह हैं ।

भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यसमिति दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प करती हैं कि हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर अथक चलते रहेंगे और देश में सुशासन और विकास की राजनीति को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। ■

कृषि क्षेत्र में सुधारों का एक नया युग शुरू

डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 9 सितंबर 2018 को कृषि पर प्रस्ताव पारित हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश के कृषि क्षेत्र में गत वर्षों में हुए सुधारों एवं किसानों के हित में उठाये गये बहुआयामी क़दमों के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना करती है तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी का हार्दिक अभिनंदन करती है। हम यहां कृषि पर पारित प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

किसानों की आय दुगुना करने की ओर मोदी सरकार के बढ़ते कदम

सबसे पहले, यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी पिछले चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसमें सुधारों का एक नया युग शुरू करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कार्यों की पूरी तरह से सराहना करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी कृषि स्तर के साथ-साथ भूमिगत स्तर पर भी किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्रस्थल में लाने और नीति को प्राथमिकता देने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए कार्यों की भी प्रशंसा करती है। इस मातृभूमि के सुपूत के रूप में किसानों के गौरव और सम्मान को वापस लाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा काम भी बेहद सराहनीय है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की एक निर्णायक भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 54.6% आबादी कृषि और इससे सम्बंधित गतिविधियों में से जुड़ी हुई है और देश के GDP का 17.6% इस क्षेत्र से आता है। आज के चार साल पहले केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले यह क्षेत्र 'संकटग्रस्त' स्थिति में था। कृषि क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों में कृषि को उसकी संकटग्रस्त स्थिति से निकालने तथा इसके पुनरुत्थान और उसमें आत्मनिर्भरता की नींव रखने के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाये। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अन्य भाजपा नेतृत्व वाले राज्य सरकारों द्वारा ढांचागत नीति निर्माण और कार्यक्रम बनाकर देश में कृषि विकास के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इन सभी प्रयासों ने पूरे देश में खेती से जुड़े समुदाय के बीच कृषि विकास की दिशा में अविश्वसनीय सफलता को दर्शाया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी कृषि क्षेत्र में किये उल्लेखनीय कार्यों में लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए उनका अभिनंदन करती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभालने के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ किसानों के कल्याण के लिए कृषि विकास की एक व्यापक नीति अपनाई है। पिछली सरकारों ने किसानों के साथ छलावा करने और उन्हें भ्रमित करने का काम करते हुए उनकी समस्याओं और चिंताओं के प्रति अत्यधिक उपेक्षा का भाव रखा। इसी उपेक्षा भाव का परिणाम था कि हमें एक ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसमें सिंचाई, विपणन, भंडारण, उर्वरक उत्पादन, वित्त और फसल बीमा जैसे बुनियादी ढांचे की कमी थी। ऐसी अव्यवस्थित कृषि नीति और सरकार की उपेक्षा के कारण देश भर के

किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही, सरकार ने लाभकारी मूल्य, सिंचाई, कृषि वित्त, विपणन, फसल बीमा और कृषि सहायक गतिविधियां आदि विषयों पर पूर्ण शक्ति और एकाग्रता के साथ काम करना शुरू किया।

जब भाजपानीत एनडीए ने केंद्र में सरकार बनायी, तब देश में खाद्य उत्पादों की कमी और आयात निर्भरता की स्थिति थी। विशेष रूप से दालें और खाद्य तेलों की कमी के चलते खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही थीं। एक तरफ, देश बड़ी मात्रा में दालों और खाद्य तेलों का आयात कर रहा था और ये आयात बहुत तेज दर से बढ़ रहे थे। देश को गेहूं, जिसमें हमने दशकों पहले ही आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी, वह भी आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हमारे किसानों के कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें गरीबी तथा ऋणधारक की स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। किसानों को लाभ पहुंचाने की बजाय कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमतें सट्टेबाजों और काले बाज़ार को लाभ पहुंचा रही थीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, इस सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का संकल्प किया और इसके प्रति कार्य करने की दिशा में तेज़ी से लग गयी। आज जब हम उस स्थिति की तुलना वर्तमान स्थिति से करते हैं तो पाते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र को न सिर्फ संकटग्रस्त क्षेत्र के दायरे से बाहर निकाला है, बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े किसानों के जीवन में बेहतरी के अनेक द्वार भी खोले हैं।

यूपीए सरकार के अंतिम 5 वर्षों (2009-14) में, कृषि के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था। जबकि, मोदी सरकार के पांचों बजट में, यह आवंटन रु 2,11,700 करोड़ तक बढ़ाया गया है; यानी, पहले से 74.5 प्रतिशत अधिक। यह वृद्धि सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि ब्याज सब्सिडी, सिंचाई, दालों के विकास, आपदा प्रबंधन, FPO, फसल बीमा जैसी सभी योजनाओं में दिखती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी: लागत + 50 प्रतिशत)

अपने उत्पादन के लिए किसानों को लाभकारी और सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करवाना इस सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। इससे पहले तक केवल 22 कृषि वस्तुओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2018-19 के बजट में, सरकार ने उत्पादन की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत और जोड़कर सभी उत्पादनों के लिए एमएसपी प्रदान करने की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2018 को 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की। इस घोषणा के तहत, लागत में 50 से 97 प्रतिशत और जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। मिसाल के तौर पर, सामान्य धान के लिए 50 प्रतिशत जोड़ा गया है। तूर के लिए 65.4 प्रतिशत जोड़ा गया है, उरद के लिए 65 प्रतिशत, बाजरा के लिए 97 प्रतिशत और कपास के लिए 58.75 प्रतिशत जोड़ा गया है। नए प्रावधानों के तहत दिया गया एमएसपी पहले की तुलना में 11.3 प्रतिशत से 52.5 प्रतिशत तक अधिक है।

सरकार द्वारा गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष पहल की गई थी और गन्ना किसानों को 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है और 8000 करोड़ रुपये का व्यापक पैकेज भी इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के लिए चीनी उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है।

एमएसपी के अलावा, किसानों को सरल प्रणाली से, बिना किसी अवरोध के अपनी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। अप्रैल 2016 में, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) योजना शुरू की गई, जिसमें 585 मंडियां अभी तक जोड़ी जा चुकी हैं। कई बाजारों में ऑनलाइन व्यापार भी शुरू हुआ है। वर्ष 2019-20 तक, इसके अतिरिक्त 425 मंडियां ई-एनएएम के तहत जोड़ी जाएंगी। इसके माध्यम से, किसान अपने उत्पादों को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं और सबसे अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत अधिक से अधिक कृषि उत्पादन मौजूदा सरकार द्वारा खरीदकर किसानों को अत्यंत लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2010-11 और 2013-14 के बीच केवल 5 लाख मीट्रिक टन तिलहन खरीदे गए थे, जबकि वर्ष 2014-15 और 24 जुलाई 2018 के बीच तक 23 लाख मीट्रिक टन तिलहन खरीदे गए हैं, जो कि पहले से 360% अधिक है। इसी प्रकार, दालों की खरीद में 35 गुना की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 16.71 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद भी NAFED और SFAC द्वारा की गई है, जो यूपीए सरकार के दौरान पहले कभी नहीं हुआ था। पिछली सरकार की तुलना में वस्त्र मंत्रालय ने पिछले 4 वर्षों में 325 प्रतिशत अधिक कपास खरीदी है। इसी तरह वस्त्र मंत्रालय द्वारा जूट की खरीद में 172 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले चार वर्षों में खरीद के माध्यम से किसानों के उत्पादन को उनका सही मूल्य दिलवाने के लिए अभूतपूर्व काम किया है।

बजटीय आवंटन: उत्पादन में बढ़ोतरी

यूपीए सरकार के अंतिम 5 वर्षों (2009-14) में, कृषि के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान था। जबकि, मोदी सरकार के पांचों बजट में, यह आवंटन रु 2,11,700 करोड़ तक बढ़ाया गया है; यानी, पहले से 74.5 प्रतिशत अधिक। यह वृद्धि सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि ब्याज सब्सिडी, सिंचाई, दालों के विकास, आपदा प्रबंधन, FPO, फसल बीमा जैसी सभी योजनाओं में दिखती है।

कृषि विकास की दिशा में निर्धारित प्रयासों के चलते, हमारा खाद्य उत्पादन वर्ष 2017-18 तक 279.51 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2010-11 और 2014-15 के बीच औसत उत्पादन से लगभग 9.35 प्रतिशत अधिक है। यूपीए सरकार के दौरान, कई वर्षों तक दालों

का उत्पादन स्थिर था और स्थिति यह थी कि 1960 में जहां देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 70 ग्राम प्रति दिन थी, वह वर्ष 2013-14 तक घटकर केवल 40 ग्राम हो गई थी। तिलहन और दालों के लगभग स्थिर उत्पादन के कारण, आयात से देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मूल्यवान विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जा रही थी। इन खाद्य पदार्थों की कमी के कारण दालों और खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ती जा रही थीं।

दालों की कीमत 150 से 200 रुपये तक पहुंच गई थी और दाल, जो आम आदमी के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं,उनकी पहुंच से बाहर हो रही थी। सरकार के व्यापक प्रयासों के कारण, जिन दालों का उत्पादन वर्ष 2013-14 में केवल 18.5 मिलियन टन था, वह वर्ष 2017-18 तक 24.51 मिलियन टन हो गया। नतीजतन, आज दालों का आयात लगातार घट रहा है और यह 2016-17 में 66.5 मिलियन टन से घटकर 2017-18 में केवल 56.5 लाख टन हो गया है, जिसके फलस्वरूप 9,775 करोड़ रुपये की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अप्रैल-मई 2018 के दो महीनों में, दालों का आयात केवल 545 करोड़ रुपये का था। दालों के मामले में देश आज लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तिलहनों का उत्पादन भी काफी बढ़ गया है और जो उत्पादन वर्ष 2010-11 और 2014-15 के बीच 265 मिलियन टन था, वह वर्ष 2017-18 में, 15.9 प्रतिशत की वृद्धि से अब 307.15 मिलियन टन हो गया है। सरकार द्वारा घोषित कीमतों और सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के कारण किसानों को अधिक से अधिक दालें, तिलहन और अन्य फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सस्ती कीमतों पर अधिक आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं को भी फायदा हो रहा है, जिससे कि व्यापारियों और कंपनियों द्वारा अटकलों के व्यापार (speculation) पर रोकथाम लग गयी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने देश में किसान की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद की है। वर्ष 2014-15 से पहले, देश में दालों में कोई आत्मनिर्भरता नहीं थी। वर्ष 2013-14 तक, 16 राज्यों के 482 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया था, जिसे वर्ष 2016-17 तक सभी 29 राज्यों के 638 जिलों तक बढ़ा दिया गया है। बजटीय आवंटन में भी वृद्धि हुई है।

कृषि विकास के लिए व्यापार नीति

किसानों को कृषि वस्तुओं के आयात के कारण होने वाले घाटे से बचाने के लिए, कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है और विशेष रूप से दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध (quantitative restrictions) लगाए गए हैं। इसके अलावा, दालों की सभी किस्मों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को नवंबर 2017 से हटा दिया गया है। चने के निर्यात को बढ़ाने के लिए 7 प्रतिशत की दर का incentive दिया जा रहा है। उत्पादन पर incentive और आयात पर नियंत्रणों के कारण, दालों का आयात घट गया है। तिलहनों के बढ़ते उत्पादन से खाद्य तेल आयात में वृद्धि दर भी घट गई है; साथ ही साथ अनेक कृषि वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 बजट में Farmers Producer Organization (एफपीओ) के लिए आवंटन किया गया है, ताकि किसानों को एकजुट किया जा सके। यूपीए सरकार के 10 वर्षों में केवल 223 एफपीओ पंजीकृत थे, जबकि मोदी सरकार के 4 वर्षों में 521 एफपीओ पंजीकृत हुए हैं। इस बीच, NABARD द्वारा 2154 एफपीओ भी पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, किसी भी तरह से किसान के शोषण के बिना contract farming को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने देश में किसान की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद की है। वर्ष 2014-15 से पहले, देश में दालों में कोई आत्मनिर्भरता नहीं थी। वर्ष 2013-14 तक, 16 राज्यों के 482 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया था, जिसे वर्ष 2016-17 तक सभी 29 राज्यों के 638 जिलों तक बढ़ा दिया गया है। बजटीय आवंटन में भी वृद्धि हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों की लम्बे समय तक आय सुनिश्चित करने के लिए, सूखे, बाढ़, तूफ़ान जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन्हें होने वाले नुकसान से बचाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत वर्तमान सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का जोखिम बहुत कम दरों पर कम हो रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पहले की किसी भी सरकार की तुलना में फसल बीमा के लिए सबसे अधिक धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक 4 करोड़ किसान शामिल किए गए हैं और कुल बीमा राशि 1,31,000 करोड़ रुपये है। जबकि वर्ष 2013-14 में यूपीए सरकार के दौरान कृषि बीमा के लिए बजटीय प्रावधान केवल 2151 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2018-19 बजट में 13,000 करोड़ कर दिया गया,अर्थात 6 गुना वृद्धि हुई है।

सॉइल हेल्थ कार्ड

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पहले की सरकारों द्वारा कभी गंभीरता से नहीं ली गई थी, जिसके कारण किसान अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार सूचित निर्णय नहीं ले पाता था। भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड के प्रावधान को 13 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब तक लगभग 15 करोड़ किसानों को देश में मिट्टी के हेल्थ

कार्ड जारी किए गए हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार गुणवत्ता वाले बीज और पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाई जा रही है।

फ़र्टिलाइज़र

यूपीए शासन के दौरान, किसान उर्वरकों (फ़र्टिलाइज़र) की कमी से जूझ रहे थे। अब उर्वरक कमी एक ऐतिहासिक बात बन गयी है। नीम लेपित यूरिया का विचार वर्ष 2014-15 से पहले किसी के मन में नहीं आया था; लेकिन अब देश के सभी किसानों को नीम लेपित यूरिया प्रदान किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पौधा संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। रसायनों का उपयोग भी काफी कम हो गया है और फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। साथ ही, गैर-खेत और अवैध उद्देश्यों के लिए यूरिया का उपयोग भी कम हो जाता है। बंद उर्वरक कारखानों की बहाली के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और सरकार अपना नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने जा रही है।

सिंचाई; प्रति ड्रॉप अधिक फसल

प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत, 'more crop per drop' के उद्देश्य से हर खेत की सिंचाई करने की योजना लागू की गई है। यह योजना सूखे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वर्ष 2010-11 और 2013-14 के बीच, 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को माइक्रो सिंचाई के अंतर्गत लाया गया था जो वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच 28.9 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई तक बढ़ गयी है। PMKSY के अंतर्गत दिसंबर 2019 तक, 76.03 लाख हेक्टेयर क्षमता के 99 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है। NABARD के तहत 40000 करोड़ रुपये के विशेष सिंचाई फंड भी बनाए गए हैं। नतीजतन, 18 योजनाओं पर काम मार्च 2018 तक पूरा हो चुका है और 47 योजनाओं पर 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया है।

कृषि ऋण

वर्ष 2013-14 में 7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण के प्रावधान को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार कृषि ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देती है, जिसके बदले में किसानों को अपने कृषि ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होता है। कई राज्य सरकारें 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी देती हैं और इसलिए किसानों को पूरी तरह से ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है। वर्ष 2013-14 में, यह ब्याज सब्सिडी केवल 6000 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2018-19 में 15000 करोड़ रुपये हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

सरकार यह मानती है कि खेती केवल बढ़ते अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना और अन्य नकदी फसलों तक ही सीमित नहीं होती है। ग्रामीण इलाकों में आय और रोजगार बढ़ाने के लिए पशुपालन, कुक्कुट, मछली पकड़ना, मशरूम उत्पादन, बांस और संबंधित उद्योग, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी, मधुमक्खी पालन, जैविक खाद आदि क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ता बन सकते हैं। इसके लिए, किसानों की आय बढ़ाने और विभिन्न योजनाओं द्वारा उनका रोजगार बढ़ाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 2018-19 के बजट में डेयरी और मछली पकड़ने में काम कर रहे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा की घोषणा की गई है। यह पहली बार हुआ है कि भूमिहीन लोगों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की गई है।

कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों और ठंडे भंडारों में बड़ा निवेश किया जा रहा है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को भी सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों और ठंडे भंडारों में बड़ा निवेश किया जा रहा है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को भी सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पशुधन विकास

आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने पशुधन की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और प्रचार के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत, रु. 546.15 करोड़ राज्यों को अब तक जारी करे जा चुके गया है। इसके अलावा दो नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (इटारसी, मध्य प्रदेश में, चिंतला देवी, आंध्र प्रदेश में), 20 गोकुल ग्राम, प्रति वर्ष 50 लाख की क्षमता वाले एक नए अत्याधुनिक (फ्रोज़ेन) वीर्य केंद्र स्थापित किया गया है। स्वदेशी नस्लों के क्षेत्र में असाधारण काम के लिए गोकू रतन और कामधेनु पुरस्कार भी शुरू किया गया है। गोबर की खाद पर मोदी सरकार द्वारा सब्सिडी देने से पशु पालक और जैविक खेती करने वाले दोनों को लाभ मिला। भेड़ पालन करने वाले किसानों कि संवृद्धि की योजना नाबार्ड के माध्यम से चलायी जा रही है जिसमें कालीन, ऊन के काम में काफी प्रोत्साहन मिल रहा है।

हरित ऊर्जा

सरकार ने एक नई जैव-इथेनॉल नीति भी शुरू की जिसका लक्ष्य हर साल 1 अरब लीटर इथेनॉल की कुल उत्पादन क्षमता के साथ परियोजनाओं की स्थापना के लिए 5000 करोड़ रुपये के निवेश को बढ़ावा देना है। एक तरफ ये नीति कृषि और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करेगी,

तो दूसरी तरफ इस का उद्देश्य देश की विशाल ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करना है। यह नीति इथानोल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के लिए गुड़-आधारित इथेनॉल उत्पादन के पारंपरिक दृष्टिकोण के मुकाबले लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास से जैव-इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है।

ऑपरेशन ग्रीन

सरकार ने देश में TOP (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत अस्थिरता को रोकने के लिए एक रोड मैप बनाया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के आवंटन को 2018-19 बजट में दोगुना करके1400 करोड़ कर दिया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टमाटर, प्याज और आलू की कीमत में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ऑपरेशंस ग्रीन के तहत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर रोड मैप तैयार करेगी कि टमाटर प्याज आलू साल भर देश के हर कोने में बिना अस्थिर कीमतों के उपलब्ध हो। 2018 के बजट में इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित किया गए हैं। 104 cold storage बनाने के अलावा, सरकार सभी 42 मेगा फूड पार्कों में कृषि परीक्षण सुविधाओं भी स्थापित कर रही है, ताकि कृषि-वस्तुओं के निर्यात को पूरी क्षमता प्राप्त हो सके।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है और कुल वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 19 प्रतिशत योगदान देता है। पिछले चार वर्षों में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2010-14 की तुलना में, 2014-18 के दौरान दूध उत्पादन 23.69 प्रतिशत बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान डेयरी किसानों की आय में भी 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सफेद क्रांति

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है और कुल वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 19 प्रतिशत योगदान देता है। पिछले चार वर्षों में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2010-14 की तुलना में, 2014-18 के दौरान दूध उत्पादन 23.69 प्रतिशत बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान डेयरी किसानों की आय में भी 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नीली क्रांति

जहां एक ओर पिछले चार वर्षों में दुग्ध क्रांति तेज़ी से बढ़ी है तो वहीं मछली उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई है। मछली, जो प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, का भारत में कुल उत्पादन वर्ष 2010-14 के दौरान 355.16 लाख टन था, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के चार वर्षों (2014-18) के दौरान, 26.01 प्रतिशत बढ़कर 447.55 लाख टन हो गया है। भारत अब मत्स्यपालन के मामले में दूसरी नंबर पर आ गया है। यह क्षेत्र, जो देश में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने देश में मत्स्यपालन क्षेत्र में मछुआरों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और उनके कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करती है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लक्ष्य गांवों में समृद्धि लाना है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अप्रत्याशित प्रगति की गई है। पूर्व सरकारों ने केवल किसानों को लाभ देने को लेकर झूठे वादे किए हैं। हालांकि, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इस कार्य को सच्चे ढंग से पूरा में काम किया। हमारे देश के मेहनती किसानों और श्रमिकों के प्रयासों के साथ सही दिशा में कृषि उत्पादन बढ़ने से और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए पूरे देश के खेती समुदाय के निरंतर और सक्रिय समर्थन के चलते श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का वादा करती है।

वर्तमान सरकार का ध्यान स्थायी ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने, किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, समग्र जैव सुरक्षा और पर्यावरणीय नुकसान की रोकथाम और एक गतिशील संयोजन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और केंद्रित पोषण सहायता में वृद्धि जैसे विषयों पर केन्द्रित है।

देश के कृषि क्षेत्र में गत वर्षों में हुए सुधारों एवं किसानों के हित में उठाये गये बहुआयामी क़दमों के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बार फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना करती है तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी का हार्दिक अभिनंदन करती है।

भाजपा नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सम्पूर्ण किसान समुदाय के लगातार समर्थन तथा सक्रिय सहयोग से इस स्थिति में और सुधार लाने का वादा करती है। ■

नए भारत के निर्माण का संकल्प

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 9 सितंबर 2018 को राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किया।

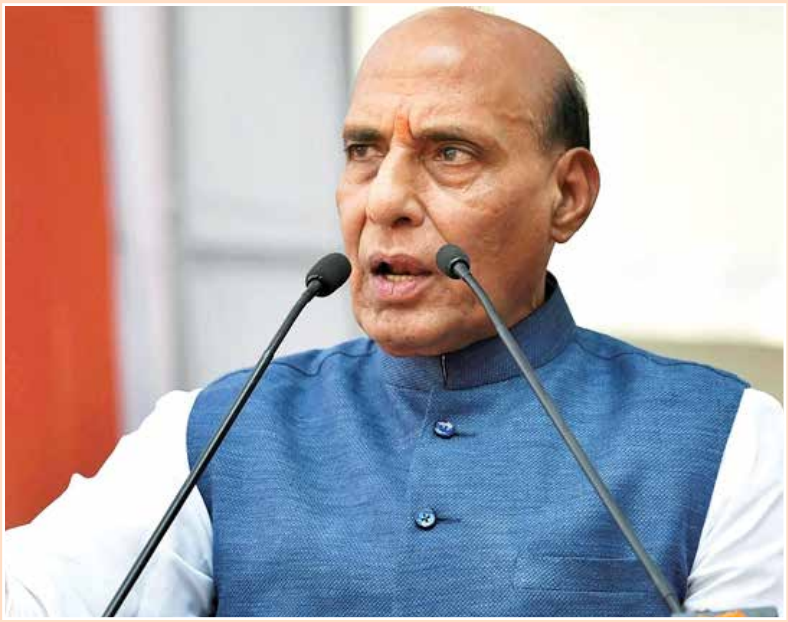

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी 130 करोड़ भारतीयों के समर्थन से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण के संकल्पों को हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। हम प्रत्येक भारतीय को भारत में हो रहे बदलाव की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बार फिर नए भारत के संकल्पों को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए एक स्वर में उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। हम यहां राजनीतिक प्रस्ताव का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 2022 के नए भारत के निर्माण के उनके दृष्टिकोण के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार और अभिनंदन करती है। 2022 वह वर्ष होगा, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा और एक नया भारत जो भूख, बेघरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। यह एक ऐसा नया भारत होगा जो एकजुट, मज़बूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। हम एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां- न कोई बेघर हो, न कोई गरीब हो, न आतंकवाद हो, न भ्रष्टाचार हो, न जातिवाद हो और न संप्रदायवाद हो।

आज जब हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं, तो निम्न आय वर्ग के लगभग एक करोड़ परिवारों को उनके अपने घर प्राप्त होने वाले हैं। अगले तीन वर्षों में देश के निम्न आय वाले 5 करोड़ से से अधिक परिवारों के पास उनका अपना घर हो और देश बेघरी की समस्या से पूर्णतया मुक्त बने, इस लक्ष्य को लेकर हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रतिबद्धता के साथ केंद्र की सरकार इस दिशा में काम कर रही है, कार्यकारिणी विश्वास व्यक्त करती है कि देश से बेघरी की समस्या से पूरी तरह निजात अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

आज जब हम यहां नए भारत पर विचार-विमर्श करने के लिए यहां बैठे हैं, तो भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मिज़ोरम का एक मध्यम आयु वर्ग का कम शिक्षित किसान, वैज्ञानिक खोजों के आधार पर बनाई गई नई नई कृषि प्रणालियों का उपयोग करके अपने खेत में मशरूम के रिकॉर्ड उत्पादन की गर्व से घोषणा कर रहा है। यही वह स्वर्णिम अवसर है जब भारत अपने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र में बहुआयामी तकनीकी खोज कर रहा है।

आज देश के अलग-अलग राज्यों से हम आशाओं की खिलती किरणों को देख पा रहे हैं। ये नए भारत की आशाओं की किरणें हैं।

राजस्थान के एक छोटे से गांव का 19 वर्षीय स्नातक छात्र कुछ नया करने के उत्साह में, अपने छोटे से खेत में पेड़ के नीचे बैठकर नव तकनीक युक्त रिमोट संचालित ट्रैक्टर चलाते हुए कहता है कि अब किसानों को कड़कती धूप में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब वे उसके द्वारा बनाये गए 1 लाख रुपये से कम लागत के रिमोट व्हील का उपयोग करके, पास के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर ऐसा कर सकते हैं। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश भर में आविष्कार के प्रयास और नई-नई खोजों की भावना का व्यापक प्रसार हो रहा है।

यह दौर देश के देश के सामान्य आदमी के मन में बढ़ते आत्मविश्वास का दौर है। महाराष्ट्र के एक रिक्शा खींचने वाले की बेटी और तमिलनाडु के एक मदरसा शिक्षक की बेटी ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रभावशाली रैंकिंग हासिल करके यह सिद्ध किया है कि वे प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी अब भारत की नई कहानी का हिस्सेदार बन रहा है। यही अन्त्योदय की सफलता का प्रमाण भी है।

विकास के मानदंडों पर नए भारत की संकल्पना बहुआयामी है। यह हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयामों को छू रहा है। देश की छः युवा महिला नौसेना अधिकारियों का एक समूह आईएनएसवी तारिणी नामक नौकायन से दुनिया का चक्कर लगाने के बाद वापस आया है, जो भारत की समुद्री क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और मजबूती का उत्कृष्ट प्रमाण है। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली युद्ध मशीन, मिग 21 लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने की तैयारी देश की तीन युवा महिला अधिकारी कर रही हैं। दूसरी तरफ भोपाल के एक चाय बेचने वाले की पुत्री एक लड़ाकू पायलट के रूप में वायु सेना में शामिल होने की तैयारी कर रही है। ये सारे उदाहरण इस बात के संकेत हैं कि भारत की महिलाएं बहुत साहस और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं।

भारत और भारतीयता के विचार आज दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की स्वीकार्यता को कार्यकारिणी एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "190 से अधिक देशों के लोग, देहरादून से डबलिन, शंघाई से शिकागो, और जकार्ता से जोहान्सबर्ग तक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न योगासन और प्राणायाम कर रहे थे और अपनी सांस को नियंत्रित कर रहे थे। भारत आज वैश्विक कल्याण का केंद्र बन गया है।"

आज का भारत बहुपक्षीय बदलावों की नई इबारतें गढ़ रहा है। इस बदलाव में देश के सवा सौ करोड़ भारतवासियों की भागीदारी है। एक ओर जहां UNHRC ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार स्थितियों पर एक अत्यधिक पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट को प्रचारित किया, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक आतंकवादी गतिविधियों के क्षेत्र अनंतनाग में हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना STAND UP INDIA की भूरि-भूरि सराहना की गई। वहां की महिला लाभार्थियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन्होंने रमजान के पवित्र महीने के दौरान हर रोज यह प्रार्थना की है कि श्री नरेन्द्र मोदी अगले पांच वर्षों के लिए पुनः प्रधानमंत्री बनें।

एक नया भारत आगे बढ़ रहा है

भारत अब अपने गांवों के धुंआ-फूंकने वाली प्रदूषणयुक्त तथा ग्रामीण जनजीवन के लिए खतरनाक चिमनियों से बाहर निकल रहा है। हम गरीब ग्रामीण परिवारों को पर्यावरण-अनुकूल LPG के चूल्हे से युक्त सम्मानपूर्ण जीवन देने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने 5 करोड़ से अधिक परिवारों को LPG सिलेंडर देकर, देश की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक धुआंयुक्त रसोई के दौर को समाप्त करने का कार्य तेजी से किया है।

नए भारत के निर्माण के संकल्पों के साथ हमने उन सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य लक्ष्यावधि से पहले पूरा किया है, जो आजादी के सात दशक बाद भी बिजली से वंचित थे। देश में सभी ग्रामीण और शहरी घरों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 'सौभाग्य योजना' शुरु की गई। इस योजना से आया बदलाव अब धरातल पर दिखने लगा है।

नए भारत के निर्माण के संकल्पों के साथ हमने उन सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य लक्ष्यावधि से पहले पूरा किया है, जो आजादी के सात दशक बाद भी बिजली से वंचित थे। देश में सभी ग्रामीण और शहरी घरों के विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 'सौभाग्य योजना' शुरू की गई। इस योजना से आया बदलाव अब धरातल पर दिखने लगा है। जहां एक ओर 99% शहरी घरों में बिजली कनेक्शन है, तो वहीं बिजली-युक्त ग्रामीण घरों का प्रतिशत जो 2011 में 55% था, अब बढ़कर 88% हो गया है।

देश के लाखों युवा पुरुषों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कुशल हाथों और सक्षम कन्धों के माध्यम से एक नया भारत आगे बढ़ रहा है। हमने मुद्रा योजना के माध्यम से 13 करोड़ से अधिक को सरल ऋण दिए हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत के युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। एक नया, आत्मविश्वासी और पूर्ण प्रशिक्षित भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। 20 एम्स, 22 आईआईटी और 20 आईआईएम से हजारों से ज्यादा कुशल डॉक्टरों और इंजीनियरों का निर्माण हो रहा है। आज एक मजबूत और स्वस्थ भारत उभर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के 'हम फिट हैं

तो भारत फिट है' अभियान के तहत लाखों लोग जुड़ रहे हैं। हमने पिछले 4 वर्षों में 120,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया है, जो मौजूदा नेटवर्क का लगभग दोगुना है। नए भारत के निर्माण की दिशा में प्रगति के नए आयाम स्थापित करते भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

आधारभूत संरचना के विकास से नए भारत का निर्माण

शहरी परिवहन: हमने पहले ही 10 शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं, और 5 और शहरों को जल्द ही इससे जोड़ा जाएगा। आज शहरी सम्पर्क मार्गों का ढांचा पूरी तरह से बदल रहा है। प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए हमारी सरकार के लिए विद्युत युक्त सार्वजनिक परिवहन हमारी अगली प्राथमिकता है। ऑटो रिक्शा जैसे विद्युत स्थानीय वाहनों के माध्यम से इस पर कार्य भी शुरू भी हो चुका है। यातायात को सुलभ बनाने के लिए हम बुलेट ट्रेन की दिशा में भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

ऊर्जा: ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें 1433 टेरावाट / बिजली उत्पादन के घंटों के साथ आज का भारत खपत से ज्यादा ऊर्जा की उपलब्धता वाला देश है। भारत में अब बिजली की कमी नहीं है।

अन्तरिक्ष में सफलता: हम इस वर्ष के अंत में चंद्रयान-II लॉन्च करने जा रहे हैं और अगले वर्ष आदित्य- एल 1 नामक एक अद्वितीय सौर मिशन भी लांच करेंगे। इस वर्ष के 12 महीनों में लगभग 12 यान लॉन्च हुए। यह प्रमाण है कि आज इसरो अपनी क्षमता में नए बदलाव और नए आविष्कार बढ़ा रहा है।

डिजिटल कनेक्टिविटी: हम 2019 के अंत तक देश के 2,50,000 गांवों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 10 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनाने के कार्य में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास 1.2 बिलियन मोबाइल फोन का आधार उपलब्ध है। इसमें 45 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन है और देश में इंटरनेट से जुड़ी आबादी पचास करोड़ से भी अधिक है। हमने डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति की है। इसके माध्यम से शासन में पारदर्शिता के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल करने की दिशा में हमें सफलता मिली है। JAM- अर्थात् जन धन, आधार और मोबाइल ने सामान्य भारतीयों के जीवन तथा शासन की कार्यप्रणाली को बदल दिया है। डीबीटी की योजनाओं ने भ्रष्टाचार को कम करने में, लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में तथा सीधा लाभ उनके खातों में पहुंचाने में मदद की है।

हम 2019 के अंत तक देश के 2,50,000 गांवों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 10 लाख किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनाने के कार्य में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास 1.2 बिलियन मोबाइल फोन का आधार उपलब्ध है। इसमें 45 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन है और देश में इंटरनेट से जुड़ी आबादी पचास करोड़ से भी अधिक है।

स्वच्छता का संकल्प: यह एक निर्विवाद सत्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता को जनांदोलन बनाया है। आज स्वच्छता जन-मन का विषय बन चुका है। शौचालययुक्त परिवारों की संख्या जो अक्टूबर 2014 में 38.7 प्रतिशत थी, वह जुलाई 2018 में बढ़कर 87.9 प्रतिशत हो गई है। अब तक अक्टूबर 2014 और जुलाई 2018 के बीच 7 करोड़ 81 लाख से ज्यादा घरेलू उपयोग के शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में से कुल 417 जिलों ने स्वयं को खुले शौच से मुक्त (ODF) घोषित कर दिया है, जिसे कार्यकारिणी एक बड़ी सफलता के रूप में देखती है। इसके अलावा 19 राज्य / केंद्रशासित प्रदेश भी 100 प्रतिशत खुले शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं। इस अभियान की वास्तविक लाभार्थी, देश की महिलायें हैं, जो अब स्वयं को पहले से अधिक सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करती हैं।

स्वास्थ्यः हमने 2018-19 के बजट में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme)' के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य-देखभाल योजना की घोषणा की है, ताकि 10 करोड़ गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को प्रति वर्ष माध्यमिक और उच्च स्तर के अस्पतालों में देखभाल के लिए 5 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत योजना' दुनिया की सबसे बड़ी और अद्वितीय योजना है।

जलमार्ग: हम अपनी नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि अनेक जलमार्गों को जल्द ही चालू किया जा सके। अगले वर्ष मार्च तक हम स्वच्छ गंगा को देखेंगे, ऐसा कार्यकारिणी को पूर्ण विश्वास है।

यह सब परिणाम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकहित के लिए अपनाई गई व्यावहारिक नीति, साफ़ नीयत और कुशल नेतृत्व के कारण संभव हुआ है और हमने यह सब कुछ रिकॉर्ड समय में हासिल किया है।

आर्थिक उपलब्धियों के अहम पड़ाव: चार वर्ष पहले हमें एक कमजोर, अपारदर्शी और पूर्णतः पूंजीवादी (crony capitalist) अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। हमारे समक्ष इसे बदलने की चुनौती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अर्थव्यवस्था के मूलभूत मानदंडों को सुधारने का कार्य किया। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी, जिसे ऑस्ट्रियाई-अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पेटर ने 'creative destruction' का नाम दिया। शम्पेटर के शब्दों में "औद्योगिक परिवर्तन की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो

लगातार आर्थिक संरचना में अंदरूनी क्रान्ति लाती है, लगातार पुरानी आर्थिक संरचना को नष्ट करती है और लगातार ही एक नई संरचना का निर्माण करती है।"

नोटबंदी, जीएसटी, दिवालियापन कानून और शोधन अक्षमता संहिता – IBC इत्यादि ऐसी योजनाएं हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक और कानूनी अनुशासन लाकर हमारी अर्थव्यवस्था में मूलभूत सुधार किये हैं।

परिणामस्वरूप एक संक्षिप्त मंदी के दौर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेजी से आगे बढ़ रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अनुमानित 7.5% GDP growth की वृद्धि दर के साथ आज दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 6.6% की वृद्धि दर के साथ चीन हमारे पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार छोटी सी अवधि में भारत में 8% से अधिक विकास दर देश में हो रहे कई संरचनात्मक सुधारों को अमल में लाकर लाई जा सकती है।

भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। विश्व के GDP में भारत का योगदान, (अमेरिकी डॉलर की मौजूदा कीमतों पर) 2014 से लगातार बढ़ रहा है। 2014 में यह 2.6 प्रतिशत था जो 2017 में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2018 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सम्भावना है।

सरकार द्वारा उठाए गए अनेक नीतिगत उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास अब बढ़ गया है, जैसाकि निम्नलिखित संकेतकों से देखा जा सकता है:

मूडी रेटिंग एजेंसी ने भारत के आर्थिक सुधारों में निरंतर हो रही प्रगति के कारण भारत की रेटिंग को BAA3 से सुधार कर भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा की स्थिरता दर्शाने वाली BAA2 पर कर दिया है। 13 वर्षों बाद हमारे देश की रेटिंग में ऐसा सुधार आया है। इससे पहले जो सुधार किया गया था वह भी एनडीए कार्यकाल (जनवरी 2004) में ही हुआ था।

मूडी रेटिंग एजेंसी ने भारत के आर्थिक सुधारों में निरंतर हो रही प्रगति के कारण भारत की रेटिंग को BAA3 से सुधार कर भारत की स्थानीय और विदेशी मुद्रा की स्थिरता दर्शाने वाली BAA2 पर कर दिया है। 13 वर्षों बाद हमारे देश की रेटिंग में ऐसा सुधार आया है। इससे पहले जो सुधार किया गया था वह भी एनडीए कार्यकाल (जनवरी 2004) में ही हुआ था।

वर्ल्ड बैंक की 2018 की Ease of Doing Business रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में भारत की रैंकिंग 30 स्थान सुधर कर 100वें स्थान पर पहुंच गई।

वर्ल्ड इकनोमिक फोरम के अनुसार, वर्ष 2017-18 में Global Competitiveness Index में 137 देशों में से भारत की रैंक 40 है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में 71 से अधिक पदों का सुधार है।

परिणामस्वरूप आज हमारे पास रिकॉर्ड $ 415 बिलियन अमेरिकन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है। इस वर्ष एफडीआई का सकल प्रवाह (inflow) 61 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। निर्यात में 20% की वृद्धि और आयात में 15% की वृद्धि हुई है।

भ्रष्टाचार, जो पहले भारत में व्यवहार का सहज हिस्सा बन गया था,वह अब सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक गायब हो गया है। आजकल भारत में कहा जाता है कि आज के भ्रष्टाचारियों को स्वयं को बचाने के लिए दर-दर, 'हांगकांग से लंदन तक' भागना पड़ रहा है। वे कुछ समय के लिए भगोड़े बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें रांची जेल में अपने साथियों के साथ रहने के लिए वापस भारत आना ही होगा।

हमारी सरकार की नई आर्थिक नीतियों ने भारत और भारतीयों दोनों को समृद्ध बनाया है। एक ऐसा समय भी होता था जब भारत को एक गरीब देश कहा जाता था। ऐसा तब था जब भारत सरकार और भारतीय दोनों ही गरीब थे। धीरे-धीरे लोग अमीर बनने लगे, लेकिन सरकार गरीब ही रही। आज 4 वर्षों के कुशल आर्थिक प्रबंधन के चलते, भारतीय लोग भी संपन्न हो रहे हैं और भारत सरकार भी संपन्न हुई है। साथ साथ देश के गरीबों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है और भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी से ऊपर उठाकर बेहतर जीवन जी रहे हैं।

जीएसटी ने भारत सरकार का राजस्व लगभग 1 ट्रिलियन रुपए - (150 अरब डॉलर) तक बढ़ाने में मदद की है। कुल करदाताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इस कारण सरकार को इस वर्ष अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को 3.3% तक घटाने का विश्वास है।

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का 3.9 प्रतिशत था, जो वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 3.5 प्रतिशत रहा और इसके वर्ष 2018-19 में 3.3 प्रतिशत होने की सम्भावना है। यदि इसकी तुलना यूपीए वर्षों में हो रहे राजकोषीय घाटे से करें तो: वर्ष 2009-10 में यह 6.5% था, फिर वर्ष 2010-11 में 4.8% हो गया, वर्ष 2011-12 में यह दोबारा बढ़कर 5.9% हुआ और वर्ष 2012-13 में 4.9% था। यूपीए के दौरान राज्यों के सकल टैक्स रेवेन्यू के 46.5 प्रतिशत से एनडीए 2 के दौरान 56% तक बढ़ने के बावजूद हमारी सरकार का प्राथमिक घाटा कभी भी जीडीपी के 1% से ज्यादा नहीं हुआ है।

कृषि क्षेत्र में, कृषि मंत्रालय के Department of Economics and Statistics द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2017-18 में 279.6 मिलियन टन अनाज का अनुमानित रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जो वर्ष 2016-17 में हुए 275.1 मिलियन टन की

तुलना में बहुत अधिक है। इस वर्ष चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल इत्यादि का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1.6 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में 305.4 मिलियन टन की नई ऊंचाई छू गया है।

वर्ष 2018-19 के खरीफ फसलों पर- 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है (A2+FL)। किसान की दशा सुधारने के लिए उठाया गया यह एक क्रांतिकारी कदम है।

केवल चार वर्षों में ही, भारत एक संयुक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। हमारे पास 4 वर्ष दंगा-मुक्त भारत का रिकॉर्ड है। देश के लगभग 160 जिलों में फैले माओवाद को आज 20 जिलों तक सीमित कर दिया गया है। हम जल्द ही एक माओवाद-मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। शहरी माओवाद के फैलाव को भी कड़े ढंग से रोका जा रहा है।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उत्तर पूर्व के आठ में से छः राज्यों में भाजपा/NDA सरकारों के बनने के कारण उत्तर पूर्व में शांतिपूर्ण वातावरण बना है। छुपे हुए नागा समूहों के साथ समझौता करने का कार्य इस क्षेत्र में स्थायी शांति बनाने की राह में प्रगति कर रहा है।

असम सरकार के 50,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा किए गए एक कठिन प्रयास के बाद नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) का प्रकाशन, राज्य द्वारा अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिक हितों के साथ साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ाने का एक महान् कार्य किया गया है। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रत्येक सही भारतीय नागरिक को आश्वस्त करना चाहता है कि अंतिम एनआरसी प्रकाशित होने पर उनमें से किसी का नाम नहीं छोड़ा जाएगा। हम भारत आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए भी कदम उठाएंगे। यह राष्ट्रीय कार्यकारी देश से बंगलादेशी या रोहिंग्या, सभी तरह के घुसपैठियों को बाहर निकालने में दृढ़ संकल्प के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करती है।

पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के कारण जम्मू-कश्मीर में प्रभावी ढंग से आतंकवाद को कम किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने पार्टी के हितों से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखकर जम्मू कश्मीर में शांति और विकास के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए उस राज्य में सरकार से भी स्वयं को अलग कर लिया है।

पिछले चार वर्षों में दुनिया में भारत का महत्व और सम्मान बहुत अधिक बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गणना विश्व के अग्रणी नेताओं में की जाती है। हमारी संतुलित तथा संवेदनशील विदेश नीति की भी चारों और सराहना की जाती है। इस संतुलन का ही परिणाम है कि हमारे संबंध इज़राइल के साथ भी अच्छे हैं और पैलेस्टाइन के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस तथा चीन के साथ भी। संवेदनशीलता के प्रमाण-स्वरूप हम दिसंबर 2017 तक एक लाख से ज्यादा विदेशों मे फंसे हुए लोगों को स्वदेश वापस लेकर आयें हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक एजेंडा तय करने वाला राष्ट्र बन गया है। मात्र 75 दिनों में 177 देशों के समर्थन से 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर मोदी जी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया जाना इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

दुनिया के साथ साथ देश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। 4 वर्षों के बाद भी, प्रधान मंत्री जी की 70%+ की लोकप्रियता-रेटिंग पारंपरिक राजनीतिक आकलन को गलत साबित करती है। कोई अन्य भारतीय नेता उनकी इस रेटिंग के करीब भी नहीं आता। 2014 से लेकर अब तक हमने 15 राज्यों में चुनाव जीते हैं और 6 हारे हैं। आज हम 20 प्रदेशों में सत्ता में हैं, जबकि विपक्ष 10 प्रदेशों में सत्ता में है; उनमें से केवल 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं।

केवल चार वर्षों में ही, भारत एक संयुक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। हमारे पास 4 वर्ष दंगा-मुक्त भारत का रिकॉर्ड है। देश के लगभग 160 जिलों में फैले माओवाद को आज 20 जिलों तक सीमित कर दिया गया है। हम जल्द ही एक माओवाद-मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। शहरी माओवाद के फैलाव को भी कड़े ढंग से रोका जा रहा है।

विपक्षी दलों को हमारे अच्छे काम और जन अनुकूल नीतियों के आधार पर हमारी सरकार की अत्यधिक सद्भावना और लोकप्रियता से बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए सत्ता प्राप्त करने की हताशा में विपक्षी दल विभिन्न विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। उनके पास न तो कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला कर सके, ना ही इसके लिए कोई रणनीति है। उनका एकमात्र उद्देश्य है "मोदी रोको"। वे चाहते हैं कि नए भारत को किसी भी तरह से नष्ट किया जाए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वर्ष 2022 तक एक नया भारत बनाने का आह्वान किया है।

भारतीय जनता पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी 130 करोड़ भारतीयों के समर्थन से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण के संकल्पों को हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। हम प्रत्येक भारतीय को भारत में हो रहे बदलाव की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बार फिर नए भारत के संकल्पों को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए एक स्वर में उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। ■

भारत को अवैध घुसपैठियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 8 एवं 9 सितंबर 2018 को संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को अवैध घुसपैठियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगी। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठ:

भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केन्द्र सरकार तथा असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार को बधाई देती है कि उन्होंने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय नागरिक (NRC) के वायदे को पूरा किया। यह कार्य भारत की सुरक्षा तथा असम के लोगों की आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति काफी महत्वपूर्ण है।

भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ही असम में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ होना शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी यह घुसपैठ लगातार होती रही, क्योंकि अलग-अलग सरकारों की इसे रोकने की इच्छाशक्ति नहीं थी। इस बेलगाम घुसपैठ के कठोर अनुपात के कारण ही असम की जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। इसके विरुद्ध असम की जनता ने 1979 से 1985 के बीच एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया और विशेष रूप से ऑल असम स्टूडेंट यूनियन – AASU के नेतृत्व में छात्र तथा युवाओं ने इस बेलगाम अवैध घुसपैठ के खिलाफ विरोध किया। घुसपैठियों को Detect, Delete & Deport करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरू किये गये इस आंदोलन में 800 नागरिक भी शहीद हुये। भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में अपनी स्थापना के समय से ही असम के लोगों के इस ऐतिहासिक संघर्ष को समर्थन दिया और उस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रही।

2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर काम शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन पूर्व सरकारों की राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस पर काम नहीं किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के तुरंत बाद दृढ़संकल्प के साथ वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया और इसी कारण अंतिम प्रारूप 31 जुलाई 2018 को पूरा हुआ। सरकार असम और उसके नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई भारतीय नागरिकता से वंचित न रहे।

इस NRC पर विपक्षी राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही आलोचना की दृढ़तापूर्वक निंदा करते हैं। ये सारी पार्टियां इस समस्या की गंभीरता को जानते थे। विपक्ष जब सत्ता में था, उसने स्वयं इसको स्वीकार

किया था कि करोड़ों घुसपैठिये असम तथा अन्य राज्यों में अवैध रूप से रह रहे हैं। विश्व का कोई भी देश घुसपैठियों को अपनी जमीन पर रहने नहीं देता, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिये विपक्षी पार्टियों ने असम तथा देश के लोगों की हितों की रक्षा का साहस नहीं दिखाया और साथ ही आज वे अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े दिख रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी बार-बार स्पष्ट रूप से कहती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को अवैध घुसपैठियों के सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगी। एक-एक घुसपैठिये की पहचान की जायेगी और नागरिकता से वंचित करने के उपरांत उन्हें निर्वासित किया जायेगा। सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को पहचानने की प्रक्रिया देश के कई शहरों में शुरू कर दी है और उनके निर्वासन के लिये उचित कार्यवाही भी की जायेगी।

भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिन्दू, बौद्ध, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं की गंभीरता को समझती है जो अपनी जान की रक्षा धर्म के सम्मान, महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा और इन देशों में उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण भारत में शरण लेने के लिये आ रहे है। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकार के नागरिकता विधेयक का समर्थन करती है। ■

हम गरीबी-मुक्त एवं वैभव-युक्त भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं: नरेन्द्र मोदी

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन 9 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सारगर्भित एवं ओजस्वी समापन उद्बोधन दिया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, हम सभी को विजय का विश्वास ले उनके साथ कदम से कदम मिलाकर 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए।

हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए समापन उद्बोधन के मुख्य अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के आखिरी दिन समापन सत्र को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप चर्चा की एवं पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जिस दल के पास परिश्रम की पराकाष्ठा पार करने वाले कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव हो, उस दल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि श्री अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, एक विचार, एक कार्यकर्ता और अपने कार्यपद्धति से हर स्तर पर एक तेजस्वी तारे के रूप में चमक रही है। श्रद्धेय श्री अटल जी को भी यह विश्वास निश्चित रूप से होगा कि जिस सपने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उस सपने को पूरा कर देश को विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करने का सामर्थ्य पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, हमें उन आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की कई पीढ़ियों ने 'भारत माता की जय' के लिए और देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, हमें भी इसी तरह देश के लिए निरंतर काम करते रहना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 'अजेय भारत, अटल भाजपा' का नारा देते हुए कहा कि हम इसी विश्वास के साथ एकजुट हो आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन अधिक उज्ज्वल रहने वाले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में बदलाव के लिए जीने वाले लोग हैं, हम देश के परिवर्तन के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए जीने वाले लोग हैं, हम अपने संस्कारों के बल पर संकल्प की पूर्ति के लिए जीने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे पास नीति भी है और रणनीति भी। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जनता के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और जब तक यह मनोभाव बना रहेगा, तब तक किसी में भी हमारे आचार और विचार को चुनौती देने का सामर्थ्य नहीं है।

विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग शासन में भी विफल रहे हैं, वे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में भी विफल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि आप चाहे मिलकर आयें या अकेले आयें, लेकिन कम से कम ये तो बताएं कि आप किस आधार पर चुनाव में हमारे सामने आना चाहते हैं – वैचारिक धरापटल के आधार पर या सरकार के कामकाज के आधार पर? उन्होंने कहा कि हम हर विषय पर विपक्ष सामना करने के लिए तैयार हैं – एक तरफ 48 माह का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की राजग सरकार के कार्यों की उपलब्धियां हैं तो दूसरी तरफ देश पर 48 साल का एक परिवार का शासन। उन्होंने कहा कि विपक्ष न तो विचार के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है, न कामकाज के आधार पर और आचार पर तो

उनमें चुनाव लड़ने का साहस ही नहीं है। इसलिए विपक्ष अब झूठ की राजनीति पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अब एक ही काम रह गया है – हर दिन एक नया झूठ बोलो और उसी झूठ को बार-बार बोलो। हमें विपक्ष के हर झूठ का सटीक जवाब देना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने पाप को भी हमारे सिर मढ़ने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष के दुष्प्रचार से अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी उपलब्धियों और 'सबका साथ, सबका विकास' के एजेंडे पर अडिग रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1975 में 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में 2014 तक क्या किया और केंद्र की भाजपा-नीत राजग सरकार ने इन साढ़े चार सालों में इस दिशा में कितना काम किया है – इस पर तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा कांग्रेस को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि एक तरफ तो हमें विपक्ष के झूठे दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ना है तो दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना है।

विपक्ष द्वारा महागठबंधन की कवायद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में हमने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है जिसके कारण 2014 के बाद से देश में हुये हर चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। देश की जनता अडिग भाव से भाजपा और राजग के साथ है। यही कारण है कि जो पार्टियां एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज साथ आने को मजबूर हो गये हैं।

साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में हमने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है जिसके कारण 2014 के बाद से देश में हुये हर चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। देश की जनता अडिग भाव से भाजपा और राजग के साथ है। यही कारण है कि जो पार्टियां एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज साथ आने को मजबूर हो गये हैं।

श्री मोदी ने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या उनका तथाकथित महागठबंधन – इनके नेतृत्व का कोई ठिकाना नहीं है, इनकी नीति अस्पष्ट है और नीयत भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष के दुष्प्रचार को जनता में एक्सपोज करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 'वन नेशन, वन ग्रिड' और 'वन नेशन, वन टैक्स' का सपना साकार किया है और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर भी डिबेट होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'मुक्ति दान' का निर्णय लिया है – जो बीमार कैदी हैं, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें मानवीय आधार पर कारागार से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि सरकार की नीतियों का आधारस्तंभ है। उन्होंने कहा कि यह एक मंत्र है जिसके आधार पर हम 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर चलते हुए देश के गांव, गरीब, किसान के कल्याण के प्रति अहर्निश समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश इस सिद्धांत से प्रभावित हैं और वे अपने उद्बोधनों में इसका उल्लेख करना नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि यह हमारी 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति का ही परिणाम है कि हमारी सरकार के चार सालों में लगभग पांच करोड़ परिवार अत्यंत गरीबी की रेखा से ऊपर आये हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल से लेकर 01 मई तक देश के लगभग 65 हजार से अधिक गांवों में हमने सात लोक-कल्याणकारी योजनाओं को हर घर में पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमारी हर योजना के केंद्र बिंदु में गरीब-कल्याण का भाव निहित है। उन्होंने कहा कि सरकार के बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से देश के नागरिकों में एक विश्वास के वातावरण का निर्माण हुआ है जहां उन्हें विश्वास है कि उनका हक़ उनको मिल कर रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की राजग सरकार ने उत्तर-पूर्व को विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा है।

'आयुष्मान भारत' योजना पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम जन-जन के कल्याण एवं उनके स्वास्थ्य की चिंता के प्रति गंभीर हैं और इसलिए एक के बाद एक योजना हम लेकर आये हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश के10 करोड़ परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ लोगों के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य का खर्च सरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि हमने स्वच्छता का अभियान शुरू किया, फिर योग को मानव जीवन का अंग बनाया, सस्ती दवाइयों की योजना शुरू की, स्वास्थ्य उपकरणों के मूल्य में कमी लाने का कार्य किया, मेडिकल की सीटें बढ़ाई, तीन लोक सभा क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम शुरू किया और अब 'आयुष्मान भारत' के माध्यम से पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मिशन मोड में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 18 करोड़ से अधिक छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2022 तक देश के हर गरीब को छत देने का अभियान हाथ में लिया है। उन्होंने कहा कि हम सादगी के धरातल पर दिव्यता के साथ गरीबी-मुक्त एवं वैभव-युक्त भारत के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, हम सभी को विजय का विश्वास ले उनके साथ कदम से कदम मिलाकर 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। ■

संस्कृति और समाज

दीनदयाल उपाध्याय

गतांक का शेष...

लेकिन कभी जब व्यक्ति प्रकृति का पालन नहीं करता, तब गड़बड़ हो जाती है। जैसे भोजन कर लिया है, फिर भी यदि किसी ने आग्रह किया तो सोचा कि जब यह इतने प्यार से आग्रह कर रहा है तो चलो थोड़ा सा और खा लें। उस वक्त यदि अपने संकोची स्वभाव का परिचय दे दिया और ज्यादा खा लिया तो इसका परिणाम होता है कि पेट ख़राब हो जाता है और पाचन शक्ति ख़राब हो जाती है। यानी यह सब हुआ प्रकृति का अतिक्रमण करने के कारण। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि इसकी कमी भी हो जाती है। जहां प्रकृति की कमी होती है, वहां भी गड़बड़ हो जाती है। एक बार की बात याद आती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक मित्र ने उनसे कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे इंग्लैंड में अकाल आ गया है। इस पर शॉ ने उत्तर दिया कि मि. चैस्टर्टन, तुम्हें देखकर अकाल का कारण भी लोगों की समझ में आ जाएगा। यानी एक ओर यदि प्रकृति का अतिरेक है तो दूसरी ओर कमी हो जाती है। तो प्रकृति के अतिरेक को बचाना चाहिए, यह किसी-किसी रूप में प्रभाव डालेगा ही। इसी को लोग विकृति कहते हैं।

यह विकृति है यानी स्वस्थ प्रकृति नहीं है। यह प्रकृति ठीक रहे, स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए कार्य करना चाहिए। जहां-जहां प्रकृति का ठीक-ठीक पालन नहीं किया जाता, वहां पर विकृति आ जाती है। इस विकृति को रोकना एक नितांत आवश्यक चीज़ है। विकृति को रोककर प्रकृति को ठीक-ठीक बनाए रखना-यह काम धर्म का है। यह पहली चीज़ है, इसलिए संस्कृति जिस पहली सीढ़ी से चढ़ती है, वह धर्म की ही सीढ़ी है।

धर्म धारण करने से है-ऐसा अपने यहां कहा गया है। समाज में किसी भी व्यक्ति की धारणा, उसका अस्तित्व धर्म के कारण ही बना रहता है। यह प्रकृति स्वस्थ बनी रहे तो धारणा बनी रहती है और उसमें कोई अड़चन भी नहीं आती। विकृति के कारण ही सब बुराइयां आती हैं तथा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लक्षण हमारे यहां बताए गए हैं। कि जब आदमी आहार-विहार करता है, तब उसके कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हमारा आहार-विहार ठीक रहे, हम प्रकृति के नियमों का पालन करते रहें, तो हम रोगों से मुक्त रहेंगे। यहां पर वास्तव में धर्म आता है। कई बार मनुष्य अपनी प्रकृति तथा धर्म के अनुसार ठीक चलता है, तब भी कई कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें मनुष्य बिना दस लोगों के नहीं कर सकता। मैं कुछ पैदा करता हूं और जो भी पैदा करता हूं, उसमें सारा, समय लगाता हूं। दूसरा अपना समय अन्न पैदा करने में लगाता है और फिर हम लोग आपस में मिलकर बांट लेते हैं कि मैंने कपड़ा पैदा किया है तो मैं अन्न के बदले में कपड़ा उसे दे देता हैं। इस प्रकार जीवन में व्यवहार चलता है। लेन-देन चलता है। दूसरे के साथ हम लोग सहयोग से काम करते हैं। इसी प्रकार समाज में और भी अनेक अवसर होते हैं, जिसको वास्तव में समाज की व्यवस्था कहते हैं। उसी के आधार पर समाज का जीवन चलता है।

सब लोग अपने-अपने कर्त्तव्य का ठीक-ठीक पालन करें, तभी यह व्यवस्था ठीक प्रकार चल सकती है। जब व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका समाधान भी खोज लिया जाता है। जैसे एक सड़क पर मोटर-गाड़ियां चलती हैं। सड़क तंग है तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाने की जरूरत है। किसी से किसी की टक्कर न हो जाए, इसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। दस लोग जब एक साथ एक जगह बैठते हैं तो उनके आपस के संबंध किस प्रकार ठीक रहेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रकृति के लिए भी यह व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने प्राकृतिक हितों का संपादन कर सकें, इस हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पर प्रयत्नों की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति इन नियमों का ठीक-ठीक संपादन कर सके। अतः राज्य आता है।

राज्य यह देखता है कि दूसरे राज्य के लोग लोगों को ठगते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। और उनका शोषण करते हैं। वे ऐसा न कर सकें, इसीलिए राज्य बीच में खड़ा हो जाता है। उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार जितनी भी व्यवस्थाएं आती हैं, वे धर्म के अंदर आती हैं। ये सब व्यवस्थाएं प्रकृति के आधार पर आती हैं। यह सब काम धर्म के आधार पर होता है।

जब हम केवल व्यक्तिगत प्रकृति पर ही ध्यान देते हैं, यानी अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि का ही विचार करते हैं और अपनी प्रकृति का विचार नहीं करते तब वास्तव में संस्कृति आती है। संस्कृति प्रकृति की व्यवस्था ठीक प्रकार से रखती है। यह धर्म से एक क़दम आगे आती है। हर पीढ़ी में

व्यक्ति की प्रकृति को ठीक बनाए रखना है। व्यक्ति की प्रकृति को समाज विरोधी न बनाना सामूहिक कर्त्तव्य द्वारा उसे कैसे पूर्ण किया जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए-ये सब कार्य संस्कृति के हैं।

इसके अतिरिक्त भी जब आदमी काम करता है, जिसमें व्यक्ति की अपनी प्रकृति का कोई विचार नहीं होता, विचार केवल समष्टि का होता है, दूसरे का होता है, जिसमें व्यक्ति परमार्थ भाव से काम करता है, यानी उसकी समष्टि की जो धारणा रहती है, समाज की जो एक विशेषता रहती है, उसके आधार पर जब वह काम करता है, तब वास्तव में संस्कृति प्रारंभ होती है। उस संस्कृति का मोटा-मोटा लक्षण यदि देखें तो यह देख लें कि मैं जो काम कर रहा हूं, वह मेरे अपने स्वार्थ में है क्या? यानी स्वार्थ का काम बुरा है, ऐसा मानने की भी ज़रूरत नहीं। स्वार्थ प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ अंशों तक आवश्यक रहता है। जैसे कोई कहेगा कि वह अपने लिए रोटी खाता है। रोटी खाने से कोई स्वार्थी कह दे, तो यह ठीक नहीं। इस अंश तक तो स्वार्थ का पालन करना ज़रूरी है। यह कोई ग़लत चीज़ नहीं, ख़राब नहीं, इसके लिए किसी का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं।

अपने यहां स्वार्थी शब्द ख़राब माना जाता है। लेकिन वास्तव में यह ख़राब वहां होता है, जब कोई अपने स्वार्थ के लिए अन्यों को बाधा पहुंचाता है। केवल जो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और उससे किसी को कोई नुक़सान भी न हो रहा हो तो वह बुरा नहीं है। यह साधारण प्रकृति है, सभी अपने लिए कार्य करते हैं। जब कोई दूसरे का बिगाड़कर अपना काम करता है, तब कहा जाता है कि वह स्वार्थी है, लेकिन जब हम संस्कृति का विचार करते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ता है कि यह काम जो कुछ होगा, परमार्थ भाव से होगा। दूसरों की भावनाओं से होगा। इसका विचार आ जाए कि इसके लिए मैं काम कैसे करूं? जहां पर यह विचार आ जाएगा, वहां पर हम कहेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी प्रेरणा अपनी संस्कृति से पाते हैं। अब यह दूसरे के भले का विचार करना मुख्य चीज़ है। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चार लोगों का काम करना अपने स्वार्थ के लिए भी हो सकता है। सामूहिक स्वार्थ का विचार करके भी हम कार्य कर सकते हैं।

सामूहिक स्वार्थ में हम यह भी सोचकर चल सकते हैं कि इसमें क्या है, सारा हिंदुस्थान ऊंचा उठाया गया तो हम भी ऊंचे उठ गए। डाकुओं का झुंड भी दूसरों के लिए काम करता है, वहां भी उनके लिए एक अनुशासन का पालन होता है। अतः जहां ऐसी चीजें होती हैं, उसे हम सांस्कृतिक नहीं कहते । जहां हमारे कार्य की प्रेरणा बिल्कुल निस्स्वार्थ हो और इसके लिए परमार्थ से भी ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि हम बिल्कुल निस्स्वार्थ भाव से काम करें और उस निस्स्वार्थ भाव में हम एक महान् ध्येय सामने रखें। एक जीवन से दूसरे जीवन को सुखी बनाने की कल्पना सामने रखकर काम करें। उसमें इतना भी स्वार्थ न हो कि उसको सुखी करने में अपने को आनंद होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को सुखी करने में अपने को आनंद होता है।

हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं और बुलाकर उसको खिला-पिलाकर उसका आदर-सत्कार करते हैं, लेकिन मन में यह भाव छिपा रहता है कि चलो, मैंने इसका आदर सत्कार किया है, यह कम-से-कम इतना तो कहेगा कि आदमी बड़ा भला है। यह दूसरों का बड़ा आदर करता है। अतिथि सेवा करने में यह बड़ा रत है। मन के अंदर जो यह आनंद वाली चीज़ है, यह तनिक भी न आए। यह भाव भी मन में न आए, तब हम कहेंगे कि हमारा संस्कृति का भाव जाग्रत् हुआ। हमारे घर में आने वाले व्यक्ति की जब हमने अच्छी प्रकार से सेवा-सुश्रुषा कर दी, यह सोचकर कि आज हम उसे खिला दें तो कल शायद वह हमें भी ऐसा ही खिलाए। तो यह सब वह है जहां पर साधारणतया प्रकति का विचार होता है, व्यापार, बुद्धि का विचार होता है। इसमें कोई संस्कृति का विचार नहीं।

जहां पर हम उसकी सब प्रकार से सेवा करें और दो मीठे शब्दों का भी विचार न करें, वही स्थान सबसे ऊंचा है। एक बार एक स्थान पर सत्संग हो रहा था। वहां पर एक सज्जन ने सबके जूते उठाकर रखने का काम अपने पास लिया। पूछने पर उसने कहा कि इस काम के लिए तो बड़े-बड़े लोग लालायित रहते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता और जिसको यह काम मिल जाता है, वह समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। मैंने पूछा कि क्या आपने इसलिए यह काम किया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भी समझ लीजिए। यानी उनके मन में यह भाव था कि इस तरह की सेवा करने से मैं सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकेगा। यह निस्स्वार्थ सेवा नहीं है, लेकिन जहां हम परार्थ भाव से स्वतः निस्स्वार्थ होकर काम करते हैं तो हम संस्कृति के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं और उसमें से हमारे अंदर की जो विशेषता है, वह प्रकट होती है।

पश्चिम के लोग यह विचार तक नहीं कर पाए। उनकी जो प्रकृति होती है, उसके अनुसार उन्होंने भौतिक जीवन तक ही विचार किया, उसके आगे उन्होंने विचार ही नहीं किया। अतः यह काम कैसे नहीं करना, यह काम कैसे करना, उसकी पद्धति क्या है? कैसे सोचना, इसका एक सीधा सा रास्ता है। यह संस्कृति का विषय जितना भी गहन हो, पर हमारे यहां पर एक पद्धति लगा दी है कि कठिन से कठिन चीज़ को भी व्यक्ति व्यवहार में ला सके, इसके लिए सीधे रास्ते बना दिए। जैसे तुलसीदासजी आए, उन्होंने कहा कि सारी चीजें छोड़कर केवल राम का भजन करो, सब दुःख मिट जाएगा। एक सीधा रास्ता बता दिया। हमने भी एक सीधा-सादा रास्ता निश्चित किया।

अपनी भारतीय संस्कृति से जीवन के अंदर जो गुण प्रकट हो सकते हैं, वे किस आधार पर प्रकट होते हैं? वे तभी प्रकट होते हैं, जब हम परार्थ भाव से जीवित रहते हैं। समष्टि की जो आत्मा है, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। जब हम निस्स्वार्थ भाव से व्यक्तित्व का चिंतन करते हुए अपनी प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखकर धर्म के आधार पर समष्टि को आगे बढ़ाने को प्रयत्नशील होते हैं, तो उस समय हमारे जीवन में कौन-कौन से गुण प्रकट होंगे, इसका यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो मैं कहूंगा कि विचार करने का रास्ता कौन सा है, जिसके प्रति हम यह कह सकते हैं कि अपने धर्म और समाज का संरक्षण कर इसकी अभिवृद्धि करेंगे। वहीं पर हमने इसका रास्ता भी बना दिया और यह कहा कि संघ कार्य निस्स्वार्थ बुद्धि से करेंगे। ■

शेष...

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : कानपुर, -जून 4, 1959)

2018-19 की प्रथम तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि

भाजपानीत राजग सरकार के कुशल प्रबंधन व विकासपरक सुधारों के चलते देश की अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आई है। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण, कृषि और रियल एस्टेट में तेजी की वजह से अप्रैल-जून में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर 8.2% रही। यह पिछली नौ तिमाही में सबसे ज्यादा है। विकास दर लगातार चौथी तिमाही में बढ़ी है। पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) में ग्रोथ 7.7% रही थी। भारत दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश बना हुआ है। दरअसल, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 31 अगस्त को वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों दोनों पर ही जारी किए।

वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बढ़कर 33.74 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में यह 31.18 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। यह 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में बुनियादी स्थिर मूल्यों (2011-12) पर तिमाही जीवीए बढ़कर 31.63 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में 29.29 लाख करोड़ रुपये था। यह 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

जिन क्षेत्रों ने वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें 'विनिर्माण', 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं', 'निर्माण' एवं 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं' शामिल हैं। 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं' और 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाओं' की वृद्धि दर क्रमशः 5.3, 0.1, 6.7 और 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के बढ़कर 44.33 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में 38.97 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह 13.8 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है। वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में बुनियादी वर्तमान मूल्यों पर जीवीए के बढ़कर 41.02 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में 36.34 लाख करोड़ रुपये था। यह 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता है।

गौरतलब है कि इस जीडीपी विकास का आधार काफी व्यापक है और यह उपभोग व्यय में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि और नियत (फिक्स्ड) निवेश में 10.0 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की बदौलत संभव हो पाया है। विशेषकर फिक्स्ड निवेश में वृद्धि अत्यंत उत्साहवर्द्धक है, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई 14.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के मुकाबले आंकी गई बढ़त को दर्शाती है। यही नहीं, यह आंकड़ा भावी विकास की दृष्टि से भी अच्छे संकेत दे रहा है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय ढांचागत सुधारों पर निरंतर जोर दिए जाने और वर्तमान नीतिगत पहलों के कारगर क्रियान्वयन को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने तथा बुनियादी वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न पहलों ने न केवल इस तेज विकास में योगदान किया है, बल्कि इसकी गुणवत्ता को भी बेहतर कर दिया है।

आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने अपने ट्वीट में कहा है, 'प्रथम तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि। 8.2 प्रतिशत

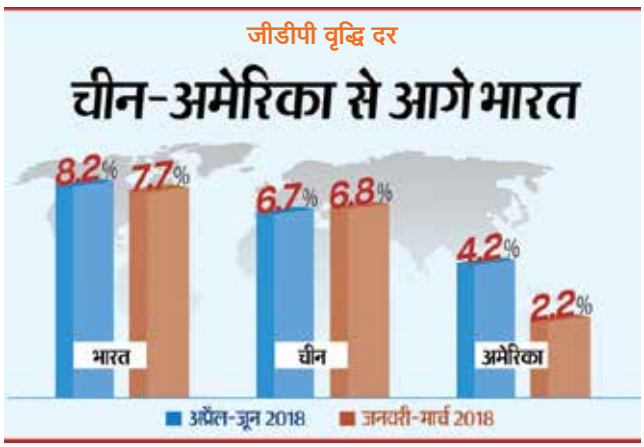

की समग्र वृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि और पूंजी सृजन में 10 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निरंतर बेहतरी का क्रम अब पूरा हो चुका है। 2018-19 में देश की विकास दर और भी तेज होनी चाहिए, जिससे भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था आगे भी बना रहेगा।'

वित्त सचिव डॉ. हंसमुख अधिया ने अपने ट्वीट में कहा है, 'वित्त वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश में लागू किए गए ढांचागत सुधार जैसे कि जीएसटी के अच्छे परिणाम अब मिलने शुरू हो गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से भी मांग में व्यापक सुधार होने के संकेत मिलते हैं। यह पिछली चार तिमाहियों में आर्थिक विकास की उल्लेखनीय गति को दर्शाती है जो क्रमशः 6.3, 7, 7.7 प्रतिशत और अब 8.2 प्रतिशत आंकी गई है।' ■

शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश

शिक्षक जितना सुयोग्य होता है शिक्षा उतनी ही सार्थक होती है, अब बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

प्रकाश जावडेकर

प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाले ज्ञान यानी लर्निंग आउटकम की बात तो खूब होती थी, लेकिन उसकी व्याख्या कभी नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने यह काम किया। लर्निंग आउटकम की व्याख्या करने से यह सुनिश्चित हो गया कि अब हर कक्षा में हर विषय में क्या ज्ञान छात्रों को होना ही चाहिए। एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम तैयार कर उसे लगभग 40 लाख शिक्षकों तक पहुंचाया और उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि वे अपनी-अपनी भाषा में लर्निंग आउटकम सुनिश्चित कर पाएं। इसके तहत छात्र, विद्यालय और अभिभावक की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। जब 25 राज्यों ने पहली से आठवीं तक परीक्षा की मांग की और प्रथम प्रयास में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को दोबारा अवसर देने का नियम बनाया तो नो डिटेंशन नीति में परिवर्तन किया गया।

यह बिल लोकसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ और अभी राज्यसभा में अनुमोदन के लिए लंबित है। हमारी सरकार का मानना है कि शिक्षक जितना सुयोग्य होता है, शिक्षा उतनी ही सार्थक होती है। हम जब सरकार में आए तब देश में 15 लाख शिक्षक ऐसे थे जो 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा रहे थे परंतु वे केवल 12वीं पास थे और उन्होंने डिप्लोमा या प्रशिक्षण नहीं किया हुआ था। करीब 8-10 वर्षों से यह समस्या चल रही थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री की पहल पर कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया कि ऐसे शिक्षकों को दो साल का एक्सटेंशन देंगे और इस अवधि में इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

हमने शिक्षकों को ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन चैनल्स के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में डिप्लोमा इन एजूकेशन करने की अपील करते हुए कहा कि आपको सरकार ने दो साल का जो एक्सटेंशन दिया है उसी में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके बाद 14 लाख शिक्षकों ने इसके लिए रजिस्टर किया। आज वे सभी पढ़ा रहे हैं। हमारा मानना है कि ये शिक्षक जितने सुयोग्य होंगे उतना ही सुधार हमारी शिक्षा व्यवस्था में होगा। हमारे शिक्षक जो कुछ हटकर अलग कर रहे हैं और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए। इसके लिए हमने जैसे पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किए वैसे ही शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन भेजे गए। जिन शिक्षकों ने नए-नए उत्कृष्ट प्रयास किए उन्हें पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इस बार 45 ऐसे शिक्षकों का सम्मान हुआ।

विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान पहले से जारी था। यह 25 साल चला। अब समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्री-स्कूल से 12वीं तक पूरी शिक्षा पर एक समग्रता से विचार हो सके, इसलिए इसका नाम समग्र शिक्षा रखा गया। इसमें तीन बड़ी पहल की गई हैं।

पहली, सभी 15 लाख सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी होगी और हर एक लाइब्रेरी को 5 से 20 हजार रुपये का अनुदान हर साल मिलेगा।

दूसरी, 'खेले इंडिया खिले इंडिया' के तहत हर स्कूल को हर साल 5 से 20 हजार तक का अनुदान खेल-कूद सामग्री के लिए दिया जाएगा। दरअसल एक बार प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में छात्रों से यह पूछा था कि यहां कितने छात्र हैं जिन्हें दिन में तीन बार पसीना आता है तो वहां जमा छात्रों में से एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। तब उन्होंने कहा था कि खेलकूद भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। खेल-कूद को बढ़ावा देने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री की इसी सोच का परिणाम है।

तीसरी पहल हर गरीब छात्र को अच्छी शिक्षा देने की है। गरीबी के कारण किसी को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिए खासकर उच्च शिक्षा में जहां फीस का भार होता है वहां शिक्षा के लिए कर्ज के ब्याज का भुगतान सरकार करती है। संप्रग सरकार के जमाने में यह राशि 800 करोड़ रुपये सालाना होती थी। पिछले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है। करीब आठ लाख विद्यार्थियों को इससे फायदा हो रहा है। आने वाले तीन साल में इस मद में हर साल 2200 करोड़ रुपये

व्यय करने का लक्ष्य है। इसके लिए 6600 करोड़ रुपये अलग से व्यवस्था की गई। इसका फायदा 10 लाख ऐसे गरीब छात्रों को मिलेगा। इन्हें शिक्षा ऋण का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस पहल का एक उद्देश्य समाज में समानता लाना भी है।

सरकार की एक बड़ी पहल स्वायत्तता को लेकर भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को हमने संसद में एक बिल लाकर शैक्षिक स्वतंत्रता दी। इसके पीछे विचार है कि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के क्रियाकलापों में दखलंदाजी के बजाय उसी संस्थान के पूर्व छात्रों को इसका दायित्व दिया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्वायत्तता की कल्पना को सबने स्वीकार किया। इसी क्रम में हमने ग्रेडेड स्वायत्तता की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। इसके तहत अब लगभग 70 विश्वविद्यालय, जिन्होंने गुणवत्ता के साथ विकास किया है उन्हें इस आधार पर विस्तार और व्यवस्था के लिए बार-बार अनुमति के लिए सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा।

दो और पहल भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रधानमंत्री जी का हमेशा बल रहता है इसलिए बजट में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की घोषणा की गई। इसके तहत नौवीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक देश भर की 15 लाख कक्षाओं में आने वाले चार वर्षों में डिजिटल बोर्ड लगेंगे। इससे शिक्षा रुचिकर और सार्थक होगी। इससे कक्षाओं में चर्चाएं अधिक गहन भी होंगी। यह एक ऐसा प्रयास है जिससे छात्रों को विषय समझने में अधिक आसानी होगी। डिजिटल बोर्ड लगाने का खाका तैयार कर हम जल्द ही उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं।

> हर गरीब छात्र को अच्छी शिक्षा देने की है। गरीबी के कारण किसी को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े, इसके लिए खासकर उच्च शिक्षा में जहां फीस का भार होता है वहां शिक्षा के लिए कर्ज के ब्याज का भुगतान सरकार करती है। संप्रग सरकार के जमाने में यह राशि 800 करोड़ रुपये सालाना होती थी। पिछले तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है।

सरकार द्वारा स्वयम प्लेटफार्म पर जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया था उसका 23 लाख से अधिक छात्र लाभ ले रहे हैं। इस पर एक हजार से अधिक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। सभी जानते हैं कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब वह नित नए शोध और अनुसंधान करेगा। चूंकि नवरचना के बिना कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए सरकार ने छह आइआइटी में रिसर्च पार्क की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को कैम्पस में न केवल अनुमति, बल्कि प्रोत्साहित देना है। इसके लिए इनक्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत की गई है।

इसी तरह उच्चतर आविष्कार योजना के तहत शिक्षक और छात्र साथ-साथ काम कर रहे हैं। देश के जो मेधावी छात्र विदेश जाकर शोध करते हैं वे यहीं देश में रुकें, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप शुरू की गई है। इस वर्ष इसके तहत 135 छात्रों का चयन किया गया है। इन सभी को प्रतिमाह एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अलावा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की अनूठी प्रक्रिया भी हमारी सरकार की एक उपलब्धि है। इसके तहत 40 हजार छात्रों ने पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में एक लाख छात्रों ने सहभागिता की। इन सभी छात्रों ने तीन महीने अध्ययन और मेहनत करके अनेक समस्याओं का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने भी इनका उत्साहवर्धन करते हुए फाइनल राउंड में उनके साथ संवाद किया। यह सारी पहल देश में शिक्षा जगत की तस्वीर बदलने की महती सोच का परिणाम है। ■

[लेखक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं]

साभार – दैनिक जागरण।

भाजपा संगठनात्मक चुनाव पर प्रस्ताव पारित

2018 में आगामी राज्य विधान सभा चुनावों और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए हाल में नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय सेंटर में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लेते हुये पार्टी के संगठनात्मक चुनाव एक वर्ष के लिये बढ़ा दिये गये हैं। इस बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अनिल जैन ने किया। बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ■

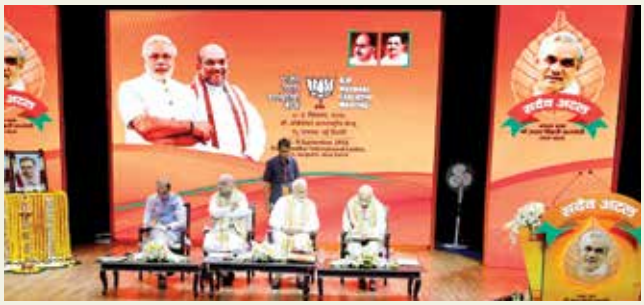

केरल आपदा के बीच कायम हुई एकता की मिसाल: के. जे. अल्फोंस

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के. जे. अल्फोंस कुशल प्रशासक के तौर पर सुविख्यात हैं। केरल कैडर से 1979 बैच के आईएएस अधिकारी रहे श्री अल्फोंस दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त रह चुके हैं। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 की समिति के सदस्य हैं। 'मेकिंग ए डिफरेंस' उनकी चर्चित पुस्तक है। हाल ही में केरल में जब विनाशकारी बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ श्री अल्फोंस की सक्रियता उल्लेखनीय रही।

पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित यातायात भवन में श्री अल्फोंस के कार्यालय में उनसे केरल प्राकृतिक आपदा, भाजपा संगठन, पर्यटन क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं आदि विषयों पर कमल संदेश के सहायक संपादक **संजीव कुमार सिन्हा** ने बातचीत की। प्रस्तुत है मुख्यांश :

हाल ही में केरल में बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। राज्य में सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। राज्य पर आए इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार किस तरह से केरलवासियों की सहायता कर रही है?

पहले दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार केरलवासियों को हर प्रकार से सहायता देने के लिए तत्पर है। इस आपदा को लेकर प्रधानमंत्रीजी ने केरल के मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत की है और निर्देश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई है। आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी मंत्रालयों की प्रतिदिन बैठक बुलाई जाती है।

पहले चरण में जब बाढ़ का प्रकोप बढ़ा तो केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केन्द्रीय सहायता के रूप में तत्काल 100 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की। उससे पहले 160 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यहां आए, स्थिति की समीक्षा की और 500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। ये जो राशियां दी गईं हैं यह तत्काल सहायता है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी क्षति हुई है, फिर केंद्र सरकार तद्नुसार सहायता राशि और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएगी। वहीं, सेना, नौसेना, अर्द्धसैनिक बल, नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स केरल के लोगों की सहायता कर रहे हैं। दूसरे राज्य भी जो कुछ सहायता कर सकते हैं, वे भी सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार पर्याप्त संख्या में विमान, हैलीकॉप्टर, बचाव जहाज आदि की मदद दे रही है और निस्संदेह राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है और हर प्रकार की संभव सहायता प्रदान की जा रही है। अतः राहत कार्य पूरी सक्रियता के साथ हो रहा है।

यह बहुत अच्छा माड्यूल रहा है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार के बीच गहरा सहयोग मिला है। भाजपानीत केंद्र सरकार का सदा से विचार रहा है, प्रत्येक राज्य को हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाए। केरल के मुख्यमंत्री ने स्वयं ही कहा है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री से पूरा सहयोग मिला है।

भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में किस प्रकार से इस संकट की घड़ी में केरल के लोगों का सहयोग कर रही है?

केरल में भाजपा कार्यकर्ता राहत कार्य में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से सेवा भारती, जो रा.स्व.सं. की समविचारी संस्था है, आवश्यकता से अधिक काम कर रही है। वे दिन–रात राहत सामग्री संग्रह के काम में जुटे हैं। घर–घर जाकर सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। जल स्तर कम हो जाने पर वे घर–घर जाकर घरों की सफाई करेंगे। वे लोगों को अपने घर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेवा भारती ने शानदार काम किया

है और आगे भी करती रहेगी। केरल बाढ़ के बारे में एक बात और उल्लेखनीय है कि केरल के लोगों ने एकता का गहरा परिचय दिया है। अन्यथा केरल राजनीतिक रूप में बहुत विभाजित रहा है। राजनीतिक विचारों के आधार पर विभिन्न क्षेत्र भी विभाजित रहे हैं। उनके अपनी–अपनी यूनियनें हैं, परन्तु इस बार सभी ने मिलकर काम किया। यह पूरे देश के लिए शानदार उदाहरण है। स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थी वितरण केन्द्र और संकलन केन्द्र में काम कर रहे हैं। दूसरे, केरल की ब्यूरोक्रेसी- आईएएस, आईपीएस आदि सभी मेहनत से काम कर रहे हैं। निःसंदेह, कई राज्यों ने सामग्री भेजी है। परिणामस्वरूप, केरल में भारी मात्रा में सहयोग राशि प्राप्त हो रही है। पूरा देश सक्रिय है। हमने सचमुच दिखा दिया है कि भारत एक है। भारत की यह एक महान भावना है जिस पर हर नागरिक को गर्व होना चाहिए।

केरल उन कुछ राज्यों में से है जहां भाजपा सरकार नहीं रही है, परन्तु हम देखते हैं कि यहां पिछले कुछ चुनावों से भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आप केरल में भाजपा का कैसा भविष्य देखते हैं?

देखिए, 2011 में विधानसभा चुनाव में भाजपा का मत 6 प्रतिशत से बढ़कर 14.65 प्रतिशत तक पहुंच गया। संसदीय चुनावों में 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक पहुंचा। पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 15 प्रतिशत मिला था। इस प्रकार वोट शेयर धीरे–धीरे बढ़ता चला जा रहा है। केरल विधान सभा में हमारा एक विधायक है। यह बहुत अच्छी बात है। मेरे विचार से लोगों को भाजपा को वोट देना चाहिए।

मोदी सरकार ने पिछले चार वर्षों में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लगभग बजट का 70 प्रतिशत गरीबों पर खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार मोदी सरकार का ध्यान साधारण लोगों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों पर कहीं अधिक है। उपलब्धियां असाधारण हैं। हमने साढ़े आठ करोड़ शौचालय बनाए, जो 72 वर्षों में बनाए गए शौचालयों की कुल संख्या से कहीं ज्यादा है। हमने 33 करोड़ गरीब लोगों के खाते खोले और इन खातों में पिछले 2 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए स्थानांतरित हुए। हमने साढ़े चार करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन बांटे, जिनसे महिलाओं को जीने का अधिकार मिला, अन्यथा महिलाएं इससे होने वाले कैंसर से मर रही थीं। आज हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हम देश के गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। उसे हम 2019 तक पूरा कर लेंगे। अब प्रत्येक घर के लिए वायदा करते हैं। इस वर्ष हम एक करोड़ से अधिक घरों को कनेक्शन सौंप देंगे। ये बड़ी बातें हैं जो हम करने जा रहे हैं। अब नवीनतम बड़ी बात सभी के लिए स्वास्थ्य की है। भारत उन चुनींदा देशों में से है, जिसकी स्वास्थ्य बीमा सभी गरीब लोगों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। 5 लाख में लोग किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। मैंने बिजली का प्रभाव जाना है। बिना बिजली वाले घरों और गांवों का अध्ययन किया है। हमने जो कुछ गरीब लोगों के लिए किया, वह केवल जीडीपी के रूप में नहीं है। इसका प्रभाव लम्बे समय तक चलता है। समुचित स्वच्छता के कारण हम लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की जीवनशैली, लोगों को दीर्घकालीन जीवनशैली की कल्पना कर सकते हैं। अच्छे शौचालय होने से 3 लाख बच्चे डायरिया से मृत होने से बच जाएंगे। कल्पना कीजिए कि किस प्रकार बिजली होने के कारण विद्यार्थी बेहतर अध्ययन कर सकेंगे, लोगों का जीवन कहीं बेहतर हो सकेगा।

हम लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। भारत विश्व में सबसे भ्रष्ट देशों में से एक था और, निःसंदेह मोदी सरकार ने पूरी तरह भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन आगे भी चलता रहेगा। इससे जीवन में बदलाव आएंगे।

पर्यटन क्षेत्र में केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां हैं?

हम विश्व में तेजी से बढ़ती पर्यटन अर्थव्यवस्था हैं। 2017 में पर्यटन की वैश्विक वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत है। पिछले वर्ष भारत में पर्यटन वृद्धि दर 14 प्रतिशत रही। विदेशी पर्यटकों का भारत आगमन 19.2 प्रतिशत तक जा पहुंचा। अतः भारत में लोगों का आगमन सबसे तेज रहा। हमने बहुत बेहतर काम किया। विदेशी पर्यटक 10 मिलियन पार कर गए और घरेलू पर्यटकों की संख्या भी अच्छी रही। इससे क्या मुझे खुशी है? नहीं, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि हमारी पांच हजार साल पुरानी सभ्यता है। हमारे पास देने को बहुत कुछ है। मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि मैं 2020 तक तीन वर्षों में 20 मिलियन पर्यटक चाहता हूं। अब हमें विदेशी पर्यटकों से 27 मिलियन डॉलर प्राप्त हो रहे हैं, जो एक लाख सत्तर करोड़ रुपए के बराबर हैं। तीन वर्षों में यह राशि दुगुनी करनी है। पांच वर्षों में हम 100 बिलियन डालर तक पहुंचना चाहते हैं। यह मेरा उद्देश्य है। आप आश्चर्यचकित होंगे यह जानकर कि चार वर्षों के मोदी शासन में भारत में पर्यटन क्षेत्र में 14.62 मिलियन रोजगार पैदा हुए। अतः देश में हम सबसे बड़े रोजगार निर्माता हैं। कांग्रेस बेरोजगारों की व्यर्थ की बातें करती हैं।

पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आगामी योजनाएं क्या हैं?

हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विदेशों में रोड शो कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों के पास पहुंचना है, उनसे बात करनी है। हम यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देशों में रोड शो कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम चीन में थे। हमारा विशेष ध्यान चीन पर है क्योंकि पिछले वर्ष 144 मिलियन चीनी लोग विदेश गए थे। चीन विश्व में सबसे बड़ा आउटडोर मार्केट है। 144 मिलियन चीनी लोगों में से केवल 2.4 मिलियन चीनी भारत में आए हैं। यह तो एक प्रतिशत भी नहीं बनता है। हमारा उद्देश्य अगले दो वर्षों में कम से कम एक प्रतिशत कुल 144 मिलियन चीनी पर्यटकों को आकर्षित करना है। अन्ततः 5 वर्षों में हम 10 प्रतिशत चीनी पर्यटकों को भारत में लाना चाहते हैं जो साढ़े चौदह मिलियन बनता है। यह संभव है, हम रोड शो कर रहे हैं और अनेक तरह से प्रयासरत हैं। ■

'छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में अटलजी का योगदान अतुलनीय'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 सितंबर को डोंगरगढ़, राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) में आयोजित "अटल विकास यात्रा" के द्वितीय चरण को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और श्री रमण सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने इस अवसर पर 'अटल विकास दूत' अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 'अटल विकास दूत' के रूप में राज्य के घर-घर जायेंगे और छत्तीसगढ़ की रमण सिंह सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को उनके साथ साझा करेंगे। 'अटल विकास दूत' प्रदेश की हर पंचायत से मिट्टी भी एकत्रित करेंगे, जिससे अटल नगर (छत्तीसगढ़ की राजधानी) में श्रद्धेय श्री अटल जी की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण होगा।

श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और उसके विकास में श्री वाजपेयी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने श्री रमण सिंह को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा कि यह श्री रमण सिंह थे जिन्होंने अटल जी की अंतिम यात्रा समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम 'अटल नगर' करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है और इसे संवारने का काम रमण सिंह जी कर रहे हैं। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर इसी तरह गतिमान बनाए रखना है तो राज्य में चौथी बार पुनः रमण सिंह सरकार और 2019 में मोदी सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह की जोड़ी छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर दिन-दुगुनी, रात-चौगुनी गति देने में सफल रही है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस की सरकार के समय जब भी रमण सिंह जी दिल्ली जाते थे, कांग्रेस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ को विकास की एक भी परियोजना के लिए निराश नहीं होना पड़ता है।

श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी सरकार से चार वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी जी, हमें आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देश को विकास से अवरुद्ध रखने वाली कांग्रेस को सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है। राहुल गांधी जी, आप हमसे चार सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि देश की जनता आपसे कांग्रेस की चार पीढ़ी का जवाब मांगती है। आजादी के बाद से देश में 50 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस का शासन रहा, 10 वर्षों तक सोनिया-मनमोहन-राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार रही लेकिन क्यों छत्तीसगढ़ के गांवों में बिजली नहीं पहुंची, क्यों किसानों को बोनस नहीं मिल पाया, क्यों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा? राहुल गांधी, पहले आप अपने कामकाज का हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को दीजिये।

मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए लगभग 3,600 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ काफी समृद्ध प्रदेश है, लेकिन कांग्रेसी कोयले की खदानें भी चोरी कर गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोयला खदानों की पारदर्शी नीलामी के कारण चार साल में छत्तीसगढ़ को लगभग 2,62,908 करोड़ रुपये

प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 पिछड़े जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने "आयुष्मान भारत" योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों अर्थात् लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने में मदद मिल सके।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री रमण सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नित नई कहानियां गढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि हमें इस बार भी केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार और राज्य में श्री रमण सिंह सरकार और भारी बहुमत से बनानी है, ताकि 2025 तक 'नवा छत्तीसगढ़' का स्वप्न साकार हो सके। ■

'भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता एक समर्पित योद्धा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 11 सितंबर को जयपुर के सूरज मैदान, राजापार्क में जयपुर शहर, जयपुर देहात, दौसा और अलवर संभाग की कुल 35 विधानसभा क्षेत्रों के 1314 शक्ति केन्द्रों से आये शक्ति केंद्र संयोजकों, पार्टी पदाधिकारियों, विस्तारकों, कार्यसमिति सदस्यों, वर्तमान एवं पूर्व जन-प्रतिनिधियों, मोर्चा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और उनसे राजस्थान के विकास के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया।

राजस्थान को वीर सपूतों की धरती बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यहां भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता एक समर्पित योद्धा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पित ऐसे शूरवीर योद्धाओं की फौज हो उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की लोक-कल्याणकारी योजनाओं एवं उनकी लोकप्रियता के कारण देश भर में जो वातावरण बना है, उसके बल पर हम अपने विपक्षी दलों से कहीं आगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उनके अपार उत्साह से यह निश्चित है कि राजस्थान में फिर एक बार पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है।

सूरज मैदान में शक्ति केंद्र संयोजकों एवं पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधान सभा चुनाव जीतेगी। मुझे लगता है कि राहुल गाँधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गाँधी को सपने देखने का अधिकार है लेकिन 2014 के लोक सभा चुनाव और उसके बाद देश भर में हुए लगभग सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। राजस्थान में भी भाजपा जीतेगी और कांग्रेस पार्टी हारेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद के पाँव की तरह है जिसे कोई डिगा नहीं सकता।

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करें कि राजस्थान में उसका नेता कौन है और उनकी नीति क्या है? यदि कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं है तो वह चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किसके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ रही है? उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा है जिसके पास केंद्र और प्रदेश में मजबूत और निर्णायक नेतृत्व है वहीं दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जिसके पास न नेता है और न ही नीतियां। ऐसी पार्टी किस मुंह से जनता के बीच में जाएगी, ऐसी पार्टी को चुनाव जीतने कोई अधिकार ही नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया, आज कांग्रेस खोजने से भी कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से जो वादे किये थे, उसे पिछले साढ़े चार सालों में पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि यही हमारी विशेषता है कि हम जो वादा करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के हर गरीब को घर देने और हर घर को बिजली देने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए 'आयुष्मान भारत' योजना लेकर आई है जिसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को अर्थात् 50 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की मुफ्त बीमा प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, आगे भी इसी तरह से देश के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आशा कार्यकर्ताओं के सामान्य मानदेय को दोगुना करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की मुफ्त सुरक्षा देने के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह ऐतिहासिक निर्णय स्वागत योग्य है। इसकी जितनी भी सराहना की जाय, वह कम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है और आज पूरा विश्व भारत के नेतृत्व को अपनी स्वीकार्यता दे रहा है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए श्री शाह ने कहा कि आप राजस्थान के विकास के लिए एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और राज्य को विकास के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ाने का संवाहक बनें। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा व अन्य अतिथिगण

नई दिल्ली में उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु की पुस्तक 'मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड-ए ईयर इन द ऑफिस' के विमोचन के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिलते अमेरिकी विदेश मंत्री श्री माइकल आर पोम्पिओ और अमेरिकी रक्षा मंत्री श्री जेम्स मैटिस

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के अवसर पर मानवता की शांति, समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना व आशीर्वाद ग्रहण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 'भविष्य की गतिशीलता' पर आयोजित विशेष विश्व सम्मेलन के दौरान 'मूव' पर पुस्तक का विमोचन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20